37 वां स्थापना वर्ष

# समवेत शिखर

बाल दिवस आज

वर्ष-37 अंक-173 | रायपुर, शनिवार 14 नवंबर 2026 | पृष्ठ : 08, मूल्य : 2.50 रुपए, ई-पेपर: samvetshikhar.com

## फर्स्ट कालम

### नई दिल्ली में छग यूसीसी की उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई

**रायपुर।** सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राऊत, शत्रुघ्न सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह तथा समिति के सचिव श्याम धावड़े उपस्थित रहे।

### जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हथियार और ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 10 गिरफ्तार

**जम्मू।** जम्मू-कश्मीर की सांबा पुलिस ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गातारू गैंग के प्रमुख सदस्यों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से गिरोह का नेटवर्क काफी हद तक ध्वस्त हो गया है। गिरोह के प्रमुख सदस्यों और अन्य आरोपियों के बीच हुए एक करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

### माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ठप ऑस्ट्रेलिया की खुफिया सर्विस-पुलिस पर असर

**शिकागो।** माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी से दुनियाभर की बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ा है। हॉन्गकॉन्ग में बैंकिंग सेवा, ऑस्ट्रेलिया में खुफिया और पुलिस सर्विस के कामकाज में परेशानी आई। इधर, जापान में सरकारी सिस्टम और फिलीपींस में अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ। कई जगह स्कूलों, अस्पतालों का कामकाज ठप हो गया। भारत में हवाई सेवाओं पर इसका असर दिखा। शुक्रवार सुबह स्पाइसजेट ने दिल्ली से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइट्स रद्द कर दीं, जबकि दरभंगा और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स लेट हुईं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने को कहा है।

### दुबई एयरपोर्ट ने स्पाइसजेट की चेक-इन सर्विस रोकी भारत आने वाली 4 उड़ानें रद्द

**नई दिल्ली।** दुबई एयरपोर्ट ने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट की चेक-इन सर्विस रोक दी है। स्पाइसजेट पर यह कार्रवाई एयरपोर्ट प्रशासन और ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी का करीब 35.85 करोड़ बकाया होने की वजह से की गई। इस कारण एयरलाइन को गुरुवार (12 नवंबर) को दुबई से दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अमृतसर आने वाली अपनी 4 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं, जिससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। वहीं, यात्रियों को समय पर फ्लाइट रद्द होने की जानकारी न देने पर दुबई की एविएशन अथॉरिटी ने भी स्पाइसजेट के अधिकारी को तलब किया है।

### जनता चाहेगी तो फिर बांग्लादेश की सत्ता संभालूंगी : शेख हसीना

**नई दिल्ली।** बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को



कहा है कि अगर जनता चाहेगी तो वे एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। हसीना ने कहा कि दिसंबर 2026 में वे बांग्लादेश लौटेंगी। उन्हें गिरफ्तारी या मौत की सजा का डर नहीं है। हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हुए हमलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शेख हसीना से उनके प्रत्यर्पण के मामले पर सवाल किया गया।

**मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंगेली जिले को दी 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात**

# गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

- 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक होगी खरीदी
- कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा



समवेत शिखर संवाददाता

**मुंगेली।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। **(शेष पेज-4 पर)**

### जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा : केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

### मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री साव

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

# असम में बस-ट्रक भिड़ंत, 26 की मौत



### ज्यादातर स्टूडेंट, गाड़ी काटकर शव निकाले, बस के 12 चालान कट चुके थे

**कांजीरंगा (ए)।** असम के काजीरंगा में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार मिनी बस और कंटेनर ट्रक में आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताया है।

असम के मंत्री और बोकाखाट से विधायक अतुल बोरा ने इसकी जानकारी दी है। टक्कर के बाद मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए। रेस्क्यू टीम ने बस काटकर शवों को बाहर निकाला। बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। लोकल मीडिया के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई गाड़ी के 12 चालान कट चुके थे। इनमें से 38,500 रुपए का जुर्माना भरा जा चुका था, जबकि 4,000 रुपए का एक चालान अब भी बकाया था। कमर्शियल गाड़ी की ओवरस्पीडिंग पर यह जुर्माना लगता है। गोलाघाट के एसएसपी स्वप्निल डेका ने न्यूज एजेंसी को बताया कि मिनी बस बोकाखाट से नगांव जा रही थी। बस तेज रफ्तार में थी। शुरुआती जांच के मुताबिक, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद घायलों को कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जोरहाट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

**असम में 5 साल में सड़क हादसों में 15 हजार से ज्यादा मौतें :** केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से 2024 के बीच राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 15,306 लोगों की मौत हुई। इनमें 2024 में सबसे ज्यादा 3,351 लोगों की जान गई। वहीं, 2023 में 3,296 और 2022 में 2,994 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि, इसके बाद की जानकारी नहीं आई है।

# विकसित भारत के निर्माण में कर्नाटक की भूमिका अहम : मोदी

**बेंगलुरु (ए)।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करने के साथ बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में कर्नाटक की भूमिका अहम होगी। श्री मोदी ने आज यहां 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा बचेगा तथा रोजगार, उद्योग और विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल सुधा यादव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पति ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। उसके बाद भी उन्होंने मां भारती की सेवा का प्रण निभाया और संसद से लेकर अब कर्नाटक में सेवाभाव से काम कर रही हैं। उन्होंने राज्यपाल को शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क सिर्फ 14



किलोमीटर था, जो आज 100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के बाद बेंगलुरु देश का तीसरा अर्बन सेंटर बन गया है, जिसने मेट्रो नेटवर्क में 100 किलोमीटर का आंकड़ा पार किया है। उन्होंने इसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवल की नई सोच का परिणाम बताया। पीएम मोदी ने बताया कि हाल ही में कर्नाटक को राज्य की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली थी और अब गोवा से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। इससे तटीय मार्ग के यात्रियों को सेमी हाईस्पीड अनुभव मिलेगा।

### मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

**बेंगलुरु।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया और बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 16,500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने आज दोपहर करीब 12.45 बजे मेट्रो की पिंक लाइन को हरी झंडी दिखाकर तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक यात्रा भी की। करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह मेट्रो लाइन कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक फैली है। इससे बेंगलुरु के शहरी परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलने, यात्रियों का सफर आसान होने और सड़क यातायात का दबाव कम करने की उम्मीद है।

# प्रधानमंत्री मेरा फोन टैप कर रहे हैं, करें आमने-सामने की बहस : राहुल गांधी

**नई दिल्ली (ए)।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनका फोन टैप कर रहे हैं और जो आरोप वह लगा रहे हैं, उन सभी के सबूत उसी फोन में मौजूद हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री को फिर आमने-सामने की बहस की चुनौती दी और कहा कि इससे साबित हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है और कौन देश विरोधी है। उनके पास इस संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं और ये सभी जानकारियां उनके फोन में हैं। श्री गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक



अन्य पोस्ट में श्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, मोदी जी, अपने ही गोदी मीडिया के दिवाली मिलन में भी टेलीप्रॉम्प्टर। लोग आपके, मंच आपका, माहौल आपका-फिर भी स्क्रिप्ट चाहिए थी। लगता है दबाव में घबरा गए हैं। खैर, कोई बात नहीं। मुझसे बहस में भी टेलीप्रॉम्प्टर ले आइए, जज भी अपनी पसंद का बैठा लीजिए। बस आइए तो सही। देश जानना चाहता है- असली देशद्रोही कौन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद में बहस की बात करती है, लेकिन जब भी उन्होंने संसद में मुद्दे उठाने की कोशिश की तब उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान विधेयक, वोट चोरी, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), चीन, पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब और एपस्टीन से जुड़े मुद्दों पर उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया। श्री गांधी ने कहा कि वह भाषण वाली बहस नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने की चर्चा चाहते हैं।

## मणिपुर में उग्रवादियों की फायरिंग में 4 की मौत, मरने वालों में दो महिलाएं

**इंफाल (ए)।** मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को उग्रवादियों ने दो गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

पुलिस के मुताबिक, हमला इम्फाल-उखरुल रोड पर न्यू हेवन इलाके में हुआ। दोनों गाड़ियों में सवार दो पुरुष और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ियों के आगे के शीशों पर गोलियों के निशान मिले हैं। इस साल फरवरी से पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं।

## अंडमान सागर में नया चक्रवाती सिस्टम बना

### ओड़िशा, आंध्र में बारिश-तेज हवा चल सकती है

**नई दिल्ली (ए)।** इसरो के सैटेलाइट ने अंडमान सागर के ऊपर बादलों की तेज गतिविधियों को कैप्चर किया है। यहां कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे नए चक्रवात बनने की आशंका है। अगले 48 घंटे में पता चलेगा कि यह सिस्टम मजबूत होकर आगे बढ़ता है या नहीं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि



यह और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो इसका नाम अकवान रखा जाएगा। यह नाम ईरान ने सुझाया है। इधर, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। इसके असर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है और सुबह धुंध छाने लगी है। राजस्थान में अगले 2 दिन आंधी-बारिश का यलो अलर्ट है। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। दिल्ली शुक्रवार को पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 दर्ज किया।

## महादेव सट्टा एप केस : सौरभ चंद्राकर 7 दिन की ईडी रिमांड पर

### ईडी ने सौरभ को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत यह कार्रवाई की है। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने सौरभ को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। उससे 19 नवंबर तक पूछताछ की जाएगी।

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सौरभ चंद्राकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है। उसके खिलाफ सीबीआई के दो और ईडी का एक मामला दर्ज है। करीब 6 हजार करोड़ रुपए के इस मामले में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, फर्जी बैंक खातों, हवाला लेनदेन और विदेशों में संपत्ति निवेश की जांच की जा रही है। ईडी ने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नेटवर्क का मुख्य संचालक बताया है। जांच में आनलाइन बुक के अलावा रेड्डी अन्ना, फेयरप्ले, स्काईएक्सजेंच और लोटस 365 जैसे आनलाइन प्लेटफार्म से जुड़े संभावित वित्तीय संबंध भी खंगाले जा रहे हैं।

**पहल** बच्चे अपने सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति बनेंगे सजग प्रहरी

# बाल संरक्षण में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल, स्कूलों में गठित होंगे 'बाल प्रहरी क्लब'

समवेत शिखर न्यूज

**रायपुर।** बाल अधिकारों की रक्षा और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 'बाल प्रहरी क्लब' गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इन क्लबों के गठन एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा



की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं तथा अधिकारों के उल्लंघन की आशंका के बारे में समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास भी किया जाएगा। प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम पांच स्थायी विषय होंगे। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से समन्वित किया जाएगा।

### शराब घोटाला केस : सिंडिकेट का हिसाब संभालने वाला विकास अग्रवाल दुबई में गिरफ्तार

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के 2,883 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में लंबे समय से फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। उसे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने दुबई में गिरफ्तार किया है। अब उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इससे जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि, उसे भारत कब लाया जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

## ►► न्यूज ब्रीफ

### जनजातीय गौरव दिवस 18 को

**कवर्धा।** कबीरधाम जिले में 18 नवंबर को जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा।



कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों के अदम्य साहस, संघर्ष, बलिदान और देश की स्वतंत्रता एवं समाज के उत्थान में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद श्री संतोष पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर जिला स्तरीय आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों को कार्यक्रम की सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयोजन गरिमामय एवं भव्य तरीके से संपन्न हो सके। जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के महत्वपूर्ण योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है।

### कलेक्टर ने धान खरीदी एवं संग्रहण केंद्रों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा



**कवर्धा।** कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज सहसपुर लोहारा विकासखंड के विभिन्न धान उपार्जन एवं संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हो रही धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने धान उपार्जन केंद्र महराजपुर, बाजार चारभांठा, राजपुर, टाटीकसा एवं धान संग्रहण केंद्र चारभांठा का जायजा लिया। उन्होंने समिति प्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों से धान खरीदी की तैयारियों, संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था तथा अब तक जारी किए गए टोकन की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए तथा किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए शुद्ध पेयजल, छायादार स्थान, मेडिकल किट, बैठने के लिए कुर्सियों तथा शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

# छठ पर्व से पहले तालाबों की सफाई में जुटीं महापौर

**रेवा तालाब में स्वयं फावड़ा चलाकर किया श्रमदान, चार प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को युद्धस्तर पर सफाई और नियमित रखरखाव के दिए निर्देश**

समवेत शिखर संवाददाता

**दुर्ग।** छठ पर्व के मद्देनजर शहर के तालाबों एवं घाटों की स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने महापौर अलका बाघमार ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। विशेष स्वच्छता अभियान के तहत महापौर ने जनप्रतिनिधियों एवं नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ शहर के चार प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेवा तालाब, शक्तिनगर तालाब, पुजारी तालाब एवं कातुलबोर्ड तालाब पहुंचकर सफाई कार्यों की स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रेवा तालाब में निरीक्षण के दौरान महापौर अलका बाघमार ने श्रमदान करते हुए स्वयं फावड़ा उठाया और तालाब से जलकुंभी एवं कचरा निकालने के कार्य में हिस्सा लिया। उनके साथ लोक कर्म



प्रभारी देव नारायण चंद्राकर एवं पार्षद मनोज सोनी ने भी फावड़ा चलाकर सफाई अभियान में श्रमदान किया। जनप्रतिनिधियों को स्वयं सफाई कार्य में जुटा देखकर निगम अमले का उत्साह भी बढ़ा।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पर्व को देखते हुए शहर के सभी तालाबों एवं घाटों में युद्धस्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए। तालाबों में जमी जलकुंभी, कचरे एवं गंदगी को प्राथमिकता से हटाने के साथ घाटों के आसपास विशेष सफाई कराई जाए। श्रद्धालुओं के आवागमन, पूजा-अर्चना एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। शहर के सभी तालाबों एवं घाटों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल निगम अमले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सहभागिता भी आवश्यक है। पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महापौर ने तालाबों की सफाई को केवल विशेष पर्वों तक सीमित न रखते हुए नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक तालाब की महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से सफाई कराई जाए, ताकि जलस्रोतों की स्वच्छता बनी रहे और नागरिकों को बेहतर वातावरण मिल सके। निरीक्षण एवं सफाई अभियान के दौरान पार्षद रंजीता पाटिल, सुरुचि उमरे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार, भाजपा जिला प्रवक्ता अरुण सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, करण करोसिया सहित नगर निगम की टीम एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

# एक दिवसीय तहसीलदारों के हड़ताल से राजस्व काम हुआ प्रभावित

### डिजिटल क्रॉप व गिरदावरी सर्वे से दूर रखने की मांग

समवेत शिखर संवाददाता

**थान खम्हरिया।** पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच आज प्रदेश तहसीलदार संघ के प्रांतीय आह्वान पर फसल गिरदावरी के मैदानी सर्वे से मुक्त रखने की मांगो को लेकर एक दिवसीय हडताल पर थे जिससे तहसील कार्यालय मे आज किसी भी प्रकरणो की सुनवाई नही हुई वही तहसील कार्यालय परिसर मे फरियादीयो को भटकते देखा गया। खबर है कि छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब फसल गिरदावरी को लेकर भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पटवारियों की अनुपस्थिति में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को मैदानी क्षेत्रों में जाकर पीवी एप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दिए जाने पर तहसीलदार संघ ने आपत्ति जताई है। संघ ने 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिकारियों को अनिवार्य मैदानी सर्वेक्षण से मुक्त रखने और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान करने की मांग भी रखी थी।



गौरतलब है कि तहसील क्षेत्र मे फसल खरीफ फसल धान कटने को है तथा 15 नवंबर से समर्थन मूल्य मे धान खरीदी प्रारंभ भी होने जा रहा है ऐसे मे तहसीलदार व पटवारीयो हडताल से डिजीटल क्रॉप सर्वे,गिरदावरी सर्वे तथा धान खरीदी जैसे कार्य प्रभावित हो रहे है।थान खम्हरिया तहसील मे 24 हजार हेक्टेयर के खरीफ फसल मे अभी भी 20-30 प्रतिशत फसल सर्वे का कार्य अधूरा पडा है।

**राजस्व और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका**–तहसीलदार संघ का कहना है कि तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अतिरिक्त मैदानी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपने से उनके नियमित कार्य प्रभावित हो सकते हैं। अधिकारियों के जिम्मे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, न्यायिक प्रकरणों के निराकरण सहित कई महत्वपूर्ण राजस्व और प्रशासनिक कार्य होते हैं। संघ ने आशंका जताई है कि यदि अधिकारियों को फसल सर्वेक्षण के लिए मैदानी क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो इन नियमित कार्यों के निपटारे में देरी हो सकती है। इससे आम लोगों को भी राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।इस प्रकार राजस्व विभाग के अधिकारीयो तथा कर्मचारीयो के लगातार हडताल की वजह से प्रशासनीक व्यवस्था लडखडाने लगी है।

# बीएसपी की कोमल ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स-2026 में सम्मानित

### 'एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप' पुरस्कार से सम्मानित

समवेत शिखर संवाददाता

**भिलाई।** इस्पात संयंत्र के परियोजना-वाणिज्यिक विभाग में कार्यरत सहायक महाप्रबंधक सुश्री कोमल मेहरा को प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स-2026 के अंतर्गत 'एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स-2026 में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

'लीडरशिप बियॉन्ड बाउंड्रीज' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में नेतृत्व, नवाचार, समावेशन और सतत विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भविष्य के नेतृत्व की चुनौतियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के बढ़ते प्रभाव तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।



सुश्री मेहरा सेल में अधिकारियों के प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और क्षमता विकास से जुड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उनके योगदान को देखते हुए सेल के निदेशक (कार्मिक) द्वारा उन्हें एसएचआरएम (सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) बेस्ट लर्नर अवार्ड तथा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2026 के अवसर पर बेस्ट लर्निंग एम्बेसडर सम्मान से नवाजा जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, सेल के ई-3 एवं ई-5 स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति परीक्षा की तैयारी के लिए व्यावसायिक संचार और परिवर्तन प्रबंधन विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए उन्हें कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने सेल के ई-1 से ई-6 स्तर तक के अधिकारियों के लिए इन विषयों पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं।

वर्ष 2008 में सेल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुश्री मेहरा वर्तमान में परियोजना प्रबंधन, निविदा एवं अनुबंध प्रबंधन तथा क्रय संबंधी गतिविधियों का दायित्व संभाल रही हैं। इसके साथ ही वे एंटी-ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम (एबीएमएस) अर्थात रिश्वतखोरी निरोधक प्रबंधन प्रणाली के लिए आंतरिक संसाधन विशेषज्ञ (इंटरनल रिसोर्स पर्सन) के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।

ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स के माध्यम से नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमिता, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रभाव, मीडिया और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। सुश्री मेहरा को मिला यह सम्मान प्रशिक्षण एवं संस्थागत क्षमता विकास के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रयासों और योगदान को रेखांकित करता है।

# धान के अलावा अन्य फसल उत्पादक किसानों को भी प्रति एकड़ 15000 रुपए आदान राशि दें सरकार

**सरकार चालू खरीफ वर्ष में भी 3100 रुपए की दर से धान खरीदी करने की चालाकी कर रही है : छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन**

समवेत शिखर संवाददाता

**दुर्ग।** छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ वर्ष 2026-27 में सरकार को धान बेचने वाले किसानों को बेचे गए धान की राशि का भुगतान घोषित एमएसपी के आधार पर करने और इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ 13839 रुपए आदान राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक एड राजकुमार गुप्त ने राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार चालू खरीफ वर्ष में भी 21 क्विंटल धान बेचने वाले किसानों का धान 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से ही धान खरीदी करने की चालाकी कर रही है।



किसान संगठन के संयोजक ने कहा है कि पिछले 3 खरीफ वर्षों में धान के एमएसपी में की गई वृद्धि की राशि का भुगतान भी किसानों को करना चाहिए क्योंकि खरीफ वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक सरकार ने किसानों का धान 3100 रूपए प्रति क्विंटल के स्थिर भाव से खरीदा है जबकि खेती की लागत और बाजार में मंहगाई 30-40त्न तक बढ़ गई है जिसके कारण किसानों के परिवार का जीवन यापन करना कठिन हो गया है, केंद्र सरकार द्वारा धान के एमएसपी में की गई वृद्धि का लाभ नहीं मिलने से पिछले 3 साल में किसानों को हजारों करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन कै संयोजक एड राजकुमार ने कहा है कि सरकार को धान के अलावा अन्य फसल के उत्पादक किसानों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए किसानों से भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसान संगठन के नेता ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जिस तरह धान धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से आदान राशि देने का निर्णय लिया गया है उसी प्रकार सरकार को धान न बेचने वाले, उद्यानिकी सहित अन्य फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की आदान राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपए की दर से आदान राशि प्रदान किया जाना चाहिए।

# सभी धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था दुरुस्त रखें, किसानों को न हों परेशानी : कलेक्टर

समवेत शिखर संवाददाता

**कवर्धा।** खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के सभी 145 धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला पंचायत सभाकक्ष में नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले अपने-अपने केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसमें किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी नोडल अधिकारी 15 नवंबर से पहले आवंटित धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन के दौरान केंद्रों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर कमियों को तत्काल दूर कराया जाए। उन्होंने जिले के संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों में विशेष निगरानी रखने और नियमित रूप से व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए।



**टोकन व्यवस्था और डिजिटल सत्यापन पर विशेष जोर**–बैठक में किसानों की सुविधा के लिए निर्धारित टोकन व्यवस्था, ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल सत्यापन की जानकारी देते हुए अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। टोकन व्यवस्था के तहत 2 एकड़ तक के किसानों को एक, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को दो तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। कुल टोकन का 70 प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से तथा 30 प्रतिशत समिति मॉड्यूल के माध्यम से जारी किया जाएगा। उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

**उपार्जन केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश**–कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने केंद्रों में विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय और मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

**किसानों की समस्याओं का करें निराकरण**–कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन, रकबा सत्यापन, टोकन अथवा धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आने पर किसानों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। संबंधित अधिकारी शिकायतों और समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर समस्या समाधान की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा मैदानी स्तर पर संवाद बनाए रखने को कहा।

**अवैध धान खरीदी पर रहेगी सख्ती, कोचियों-बिचैलियों से खरीदी नहीं**–कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के लिए सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में कोचियों, बिचैलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी नहीं होनी चाहिए। खरीदी कार्य में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**बारदाने और धान की गुणवत्ता पर भी रहेगी नजर**–कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में नए एवं पुराने बारदानों के निर्धारित अनुपात में उपयोग, धान की गुणवत्ता और निर्धारित वजन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रत्येक कट्टे में निर्धारित मात्रा में धान भरने तथा तौल में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदी गई धान की मात्रा का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए।

# सरकार का मास्टर स्ट्रोक : किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 13839 रुपए की आदान राशि

**भाजपा सरकार ने कहा-हम किसानों के हितैषी, विपक्ष ने कहा-ये केवल छलावा**

समवेत शिखर संवाददाता

**साजा।** राज्य शासन ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के लिए बड़ा दांव खेला है,किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए बड़ी घोषणा के साथ ही पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एकसमान आदान सहायता राशि देने की घोषणा की है। उक्त घोषणा से प्रदेश के किसानों में हर्ष है,जबकि मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल ने इसे केवल छलावा बताया है। विवरण वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स में उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को यह सहायता प्रदान की जाएगी।



**योजना की ख़ास मुख्य बात**–योजना की खास बात यह है कि किसानों को आदान सहायता का लाभ लेने के लिए प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम धान उपार्जन सीमा 21 क्विंटल की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसान निर्धारित क्षेत्र से कम मात्रा में भी धान बेचता है, तब भी उसे उसके पूरे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने दो एकड़ में धान की फसल लगाई है और वह समितियों में निर्धारित अधिकतम झाड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे दो एकड़ के हिसाब से 27,678 रुपये की आदान सहायता प्राप्त होगी।

**एग्रिस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे जरूरी**–योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रिस्टैक में पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के बोए गए रकबे का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। हालांकि, दूरस्थ क्षेत्रों में जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया है, वहां किसानों को राहत देते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि दी जा सकेगी। वहीं, ऐसे किसान जिन्होंने खरीफवर्ष 2025-26 में धान का विक्रय नहीं किया था, लेकिन खरीफ वर्ष 2026 में धान बेचने के लिए समितियों में पहुंचेंगे, उनके बोए गए रकबे का जिला कलेक्टर द्वारा विशेष सत्यापन कराया जाएगा।

**टोकन जारी कराते समय करना होगा आवेदन**–शासन ने योजना के तहत पारदर्शी भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी निर्धारित की है। किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना का आवेदन करना होगा। इसके बाद पात्र किसानों को आदान सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

**ग्रीष्मकालीन धान पर नहीं मिलेगा लाभ**–जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल खरीफ वर्ष 2026 में बोए गए धान पर ही मिलेगा। ग्रीष्मकालीन धान की फसल को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

**विपक्ष ने बताया छलावा**–

प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल ने इस घोषणा को छलावा कहा है,जारी व्यक्तव्य में कहा है कि इससे पूर्व भी इस सरकार में अनेक घोषणाएं हुई है जो या तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया या तो दम तोड़ दिया है ये सरकार अभी तीन वर्षों के कार्यकाल में आमजनों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इन्होंने आगे कहा कि आमजन और किसान अब किसी बहकावे में नहीं आकर हित अहित को अच्छे से समझने लगी है।

# किसानों की समस्याओं और राजस्व अधिकारियों की मांगों को लेकर वोरा ने दिया कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ को समर्थन

समवेत शिखर संवाददाता

**दुर्ग।** प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे (ष्ठ्ष्ट्स्), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री एवं धान खरीदी से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा 13 नवंबर को आयोजित एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने संघ के पदाधिकारियों एवं आंदोलनरत तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों से मुलाकात कर उनकी मांगों को अपना समर्थन दिया।



उन्होंने कहा कि प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राजस्व विभाग के न्यायालयीन कार्यों से लेकर किसानों की समस्याओं के निराकरण और शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में जब तकनीकी अधिकार और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तब अधिकारियों पर जवाबदेही डालना व्यावहारिक नहीं है। शासन को उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर आवश्यक तकनीकी सुविधाएं, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

वोरा ने कहा कि किसानों का हित और प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारु संचालन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसानों को धान विक्रय और शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए राजस्व, कृषि, खाद्य एवं सहकारिता विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने शासन से संघ द्वारा उठाई गई मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए तकनीकी विसंगतियों का शीघ्र निराकरण करने और किसानों के वास्तविक धान रकबे का सही सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग की। अरुण वोरा ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों और प्रशासनिक अधिकारियों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए उनकी आवाज उठाना आवश्यक है।

## न्यूज ब्रीफ

### श्री सीमंधर स्वामी जैन मंदिर में ज्ञानपंचमी की पूजा करेंगे बच्चे व श्रावक श्राविकाएं

**रायपुर।** खरतरगच्छाधिपति आचार्य श्री जिनमणिप्रभ सूरीश्वर जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व चमत्कारी श्री जिनकुशल सूरि जैन दादाबाड़ी में आज शनिवार को जैन धर्म के बच्चे श्रावक श्राविकाएं सम्यक ज्ञान की पूजा आराधना करेंगे । श्री सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष बैद व महासचिव महेन्द्र कोचर ने बताया कि ज्ञानपंचमी के अवसर पर पवित्र शास्त्रों व ज्ञान के महत्व को पहचानने के लिए धार्मिक पुस्तकों की पूजा सफाई व सम्मान करते हैं । इस दिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है । ज्ञानपंचमी के दिन से पंचमी का उपवास आरम्भ किया जाता है । यह शुक्ल पक्ष की पंचमी को पांच वर्ष पांच माह के लिए उपवास का संकल्प लिया जाता है । ज्ञानपंचमी के अवसर पर शनिवार को महाविदेह आराधना केन्द्र में जैन शास्त्र , ज्ञान भंडार की पुस्तकें व ज्ञान के उपकरण सजाए जाते हैं । प्रातः से बच्चे व बड़े सभी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु पूजन व चैत्यवंदन व अन्य क्रियाएं करने आते हैं । ट्रस्टी नीलेश गोलछा व डॉ योगेश बंगानी ने बताया कि ज्ञान पंचमी के अवसर पर शनिवार को ज्ञान पूजा व नवांगी पूजा करने वाले बच्चों को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जावेगा । खरतरगच्छ महिला परिषद की राष्ट्रीय संगठन मंत्री मंजू कोठारी ने बताया कि ज्ञानपंचमी के दिन कई श्रावक श्राविकाओं द्वारा मौन उपवास रखकर शास्त्रों व ज्ञान के उपकरणों की आराधना की जाती है ।

### मंत्रिपरिषद बैठक 18 नवंबर को

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास/कार्यालय सिविल लाईन रायपुर में आयोजित होगी।

### रायपुर शहर को स्वच्छता में छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग प्राप्त होना गौरव की बात है : गायत्री चंद्राकर

**रायपुर।** रायपुर शहर को स्वच्छ भारत मिशन के



अंतर्गत स्वच्छता में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग प्राप्त होना सभी शहरवासियों और प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। यह रायपुर शहर के नागरिकों की जागरूकता के फलस्वरूप है. वही यह स्वच्छता कर्मियों की मेहनत, नगर निगम प्रशासन के नीतिगत निर्णय एवं जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास का परिणाम है, जो आज रायपुर शहर को स्वच्छता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। रायपुर नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री चंद्राकर ने स्वच्छ भारत मिशन अतर्गत रायपुर शहर को स्वच्छता में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग भारत सरकार की ओर से प्राप्त होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव और रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित रायपुर नगर पालिक निगम के समस्त वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधियों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनायें दी हैं।

### एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे तहसीलदार-नायब तहसीलदार

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच तहसीलदार और नायब शुक्रवार को तहसीलदारों ने भी एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर 13 नवंबर को प्रदेशभर के अधिकारी काम पर नहीं पहुंचे। इसके चलते रायपुर समेत कई जिलों में राजस्व कोर्ट नहीं लगे और नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन जैसे मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। संघ का कहना है कि एग्रीस्टैक, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग है। इन गड़बड़ियों के कारण किसानों के काम अटक रहे हैं। खासकर 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन और टोकन को लेकर परेशानी बढ़ रही है। संघ के अनुसार, एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों का अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित है। पटवारियों के 13 अक्टूबर से हड़ताल पर होने के कारण इन आवेदनों को आगे बढ़ाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों के आवेदन अटके हुए हैं। वहीं, पीवी ऐप में किसानों का भौतिक सत्यापन करने के बाद भी उनके मामले डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं। इस तकनीकी समस्या के कारण किसानों के धान खरीदी के टोकन नहीं कट पा रहे हैं। संघ का कहना है कि जब मौके पर सत्यापन हो चुका है तो पोर्टल पर भी उसकी स्थिति अपडेट होनी चाहिए, ताकि किसानों को परेशानी न हो। संघ ने इन समस्याओं को लेकर पहले भी मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के सचिव को पत्र देकर समाधान की मांग की थी।

# नागरिकों और विद्यार्थियों के आधार व बायोमेट्रिक अपडेट कार्य को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्य सचिव

**उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आधार सेचुरेशन और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर**

**स्कूलों में चलाए जाएंगे विशेष अभियान**

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो। बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची प्रकाशित

समवेत शिखर न्यूज

**रायपुर।** भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जा रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027) के तहत 12 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचन नामावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा ईसीआई नेट मोबाइल एप्प एवं वोटर पोर्टल पर भी मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची ऑनलाइन प्रकाशित कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि 12 नवम्बर को प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में 01 करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 94 लाख 86 हजार 635 पुरूष मतदाता, 95 लाख 31 हजार 721 महिला मतदाता और 412 थर्ड जेंडर सम्मिलित हैं। उन्होंने मतदान केन्द्रों की संख्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि युक्तियुक्तकरण 02 नवम्बर 2026 के पूर्व प्रदेश में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 27 हजार 196 थी, जबकि युक्तियुक्तकरण के पश्चात् 47 नए मतदान केन्द्र स्थापित किए गए तथा 389 मतदान केन्द्रों का विलोपन किया गया। इस प्रकार प्रदेश में अब मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 26 हजार 854 है, जिनमें 5 हजार 876 शहरी क्षेत्रों में और 20 हजार 978 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

निर्वाचक नामावली में ऐसे चेक करें अपना नाम- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 12 नवम्बर को प्रकाशित निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। इसके लिए ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से चेक किया जा सकता है। इसके अलावा वोटर पोर्टल के जरिए अलावा अपने नजदीकी मतदान केन्द्र के बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन चेक भी कराया जा सकता है।

# उप मुख्यमंत्री साव आज पथ विक्रेताओं से करेंगे संवाद

- **नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन**
- **उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों और निकायों का होगा सम्मान, लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे**

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव 14 नवम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कर रहे पथ विक्रेताओं से सीधा संवाद करेंगे और लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे। महोत्सव में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान से जोड़ने विशेष सत्र भी आयोजित किया गया है। इनके साथ ही फूड स्टॉल, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी महोत्सव में होंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम थीम पर आयोजित स्वनिधि महोत्सव 14 नवम्बर को सुबह दस बजे से साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। महोत्सव का संदेश आत्मनिर्भर भारत, सशक्त शहरी विकास, स्वरोजगार से नई संभावनाएं% रखा गया है। महोत्सव में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव जानेंगे। वे पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों एवं उनकी शाखाओं को सम्मानित करेंगे। योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली नगरीय निकायों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि महोत्सव में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न बैंकों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारी जानकारी देंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा डिजिटल भुगतान अभियान के बारे में बताया जाएगा। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी होंगे।

# आज चुनाव हुए तो एक इनोवा में सिमट जाएगी भाजपा : भूपेश बघेल

**धान खरीदी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, पटवारी हड़ताल और ओबीसी जनगणना को लेकर उठाए सवाल**

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी 15 नवंबर के छत्तीसगढ़ दौरे पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा है कि आगामी 15 तारीख को ही बिहार का लोक पर्व छठ पूजा है, पहले नितिन नबीन यह पर्व अपने निर्वाचन क्षेत्र में मनाया करते थे लेकिन उपचुनावों में हार के बाद से वे डरे हुए हैं, इसलिए अब वहां जाने से भी घबरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कुशासन से हर वर्ग व्यथित है, किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी, कर्मचारी सब पीड़ित हैं, आज यदि चुनाव हो जाए तो भाजपा के विधायक एक इनोवा के लायक ही रह जाएंगे।

निकाय चुनाव को प्रभावित करने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि जेन-जी का बुखार भाजपा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग को भी चढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा मतदाताओं के साथ बड़ा षड्यंत्र किया गया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हैं। वहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 25 हजार नए वोटर्स के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। यह सरकार जेन-जी यानी युवा मतदाताओं से डरी हुई है। लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। यदि नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे तो वे चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बघेल ने कांग्रेस की ओर से मांग की कि मतदाता सूची की गड़बड़ियों को तत्काल सुधारा जाए और छूटे हुए नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। भिलाई नगर निगम चुनाव से पहले मतदाता सूची में भारी अनियमितता की गई है। बिना परिसीमन के लगभग 25,000 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिससे वे मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उनके द्वारा आवाज उठाने के बाद चुनाव आयोग को सुधार के लिए तिथियां बढ़ानी पड़ीं, लेकिन गड़बड़ी को अब तक सुधारा नहीं गया है। धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी।

# शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 22 वर्षों से 29 पद रिक्त, नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश के एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में वर्ष 2004 से रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता के पदों पर अविलम्ब नियमित भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा है।

डॉ. महंत ने पत्र में बताया कि वर्ष 2003 में महाविद्यालय की स्थापना के समय 44 स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 26 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और एससी/एसटी के 11, ओबीसी के 3 तथा सामान्य वर्ग के 4 सहित कुल 18 पद रिक्त रह गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 2004 में नियुक्त 26 सहायक प्राध्यापकों / व्याख्याताओं में से वर्तमान में केवल 15 ही कार्यरत हैं। इस प्रकार महाविद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जिन पर पिछले 22 वर्षों से कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने चिंता जताई कि शिक्षकों की इस भारी कमी से महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध कार्य और ओ.पी.डी. में आने वाले गरीब व मध्यम वर्गीय मरीजों के उच्च स्तरीय दंत उपचार पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन रिक्त पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से तत्काल नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएं।

# मंजूरी प्राप्त निविदा वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने के निर्देश

- **लोक निर्माण विभाग के सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा**
- **ठेकेदारों से बेहतर समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने कहा**
- **आरटीओ और एसपी कार्यालयों के साथ मिलकर ब्लैक-स्पॉट्स तत्परता से दूर करने के दिए निर्देश**

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में बस्तर संभाग में आर.आर.पी. और आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आर.टी.ओ. और एस.पी. कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सी.आई.आर.एफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पीडब्लूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और अप्लाइंसेस उपयोग करने को कहा। उन्होंने उपकरणों, भवनों एवं परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसम्बर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित भुगतानों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा।

# विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को ओएनओएस के माध्यम से 13 हजार शोध पत्रिकाओं तक मिली पहुंच

- **इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न**

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धता तथा इसके प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल के माध्यम से केंद्रीकृत सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत देशभर के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध प्रकाशनों एवं अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना प्रारंभ की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इसे स्वीकृति प्रदान की तथा इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। योजना के प्रथम चरण (2025-2027) के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यू.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, पादप संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध एवं वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग एवं बहुविषयक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ओ.एन.ओ.एस योजना के प्रभारी डॉ. एस.के.त्रिपाठी ने इस योजना का महत्व बताते हुए कहा कि ओ.एन.ओ.एस योजना कृषि अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक शोध तक पहुंच उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इसका प्रभावी उपयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग तथा कृषि तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान कर सकता है। विश्वविद्यालय में ओ.एन.ओ.एसयोजना के अधिकतम उपयोग के लिए इसके पंजीकरण एवं क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

# मधुकर जोशी की आंखों से दुनिया देख रहे दो लोग

**महाराष्ट्र मंडल के आजीवन सभासद ने पहले ही नेत्रदान करने का लिया था संकल्प**

समवेत शिखर न्यूज



**रायपुर।** महाराष्ट्र मंडल के आजीवन सभासद मधुकर हरिभाऊ जोशी की आंखों से अब दो लोग दुनिया देख रहे हैं। हाल ही में दिवंगत हुए मधुकर जोशी ने पहले ही नेत्रदान का संकल्प लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। छोटे बेटे अनिल जोशी के पद्मनाभपुर स्थित निवास स्थान पर उनके देह त्यागने के बाद मेडिकल टीम ने नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की।

मूलत : महाराष्ट्र के परतवाड़ा निवासी मधुकर जोशी ने इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में टेक्निकल सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। मिलिंद और अनिल के पिता मधुकर काले की लगन, मेहनत, ईमानदारी से जल्दी ही वे महाराष्ट्र के अपने साथियों नरहर देव, सुलभ दूध भंडार वाले श्रीधर येलणे और दिगंबर आगाशे के साथ सामाजिक कार्यों में लगे रहे। मिलनसार व्यवहार के कारण समाज में उन?होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली। कम आय में खर्चों का उत्तम नियोजन उनसे सीखा जा सकता था। अपने परिवार की ही तरह कई परिवारों को बेहतरीन जिंदगी जीने का प्रेरक तरीका भी वे सिखा गए। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने बताया कि 80 वर्ष की आयु से प्रतिवर्ष आजीवन सभासदों के जन्मदिन पर मंडल के सम्मान की परंपरा का मधुकर जोशी ने खुले दिल से स्वागत किया था और कहा था कि बुजुर्गों के जन्मदिन पर मंडल की ओर से सम्मान करने की यह पहल अनुकरणीय तो है ही, साथ ही जिंदगी में उनके महत्व को भी साबित और स्थापित भी करती है। उन्होंने कहा कि 'मैं तो सम?मान के साथ 20 शाल लेकर ही यानी आयु का शतक लगाकर ही मानूंगा। लेकिन 95 वर्ष की आयु में ही मधुकर जोशी का निधन हो गया। यह जोशी परिवार के लिए दुःख की घड़ी में भी संतुष्टि की बात है कि उनके नेत्रदान करने की वजह से आज दो स्वस्थ लोगों की अंधकारमय जिंदगी में रोशनी लौटी है।

**शिखर बने उतुंग शिखर, अपने प्रताप से।**
**डरे कभी वह नहीं, किसी के उग्र शाप से।।**

## संपादकीय



# गर्म होती दुनिया

आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभावों का त्रास झेल रही है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा और चक्रवात के बढ़ते क्रम हमारे समय का यथार्थ हैं। यह साल लगातार गर्म साबित हो रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 उपलब्ध मौसम इतिहास के सबसे चार गर्म वर्षों में शुमार है। इस साल सितंबर तक का वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। इस अप्रत्याशित तापमान वृद्धि की वजह 'अलनीनो' असर कहा जा रहा है, जिसके दिसंबर तक चरम पर पहुंचने की आशंका है। निस्संदेह दुनिया में अनियंत्रित विकास ने भी तापमान बढ़ाया है, जो मौसम में आने वाले अप्रत्याशित बदलावों का अहम कारक है। अमेरिका समेत तमाम विकसित देशों ने विकास के लक्ष्यों हेतु पर्यावरण के प्रश्न को नजरअंदाज किया है।

इंसानी लालच व मुनाफाखोरी के औद्योगिक विकास ने अंधाधुंध कार्बन उत्सर्जन करके ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों को बढ़ाया है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों से उपजी त्रासदी झेल रहे ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विकसित देश विमुख हो जाते हैं। इसका सारा बोझ आखिरकार विकासशील व गरीब मुल्कों पर पड़ जाता है। ऐसे विषम हालात में तुर्किये में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में उम्मीद की किसी भी किरण पर संदेह के बादल छाए हुए हैं। वैश्विक भू-राजनीतिक हालात संभावना को मुश्किल बना रहे हैं। दुनिया में कई युद्धों और अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण नीतियों से विमुखता के चलते सम्मेलन से सार्थक नतीजों की उम्मीद कम ही है। हालांकि, अलनीनो मौसम प्रणाली का असर अभी चरम पर पहुंचना बाकी है, लेकिन नेपाल की भयावह त्रासदी ने आसन्न संकट का चित्र उकेर दिया है। निस्संदेह, 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' यानी सीओपी-31 की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें जलवायु संरक्षण संबंधी बहुपक्षीय सहयोग की कमी और परस्पर विरोधी लक्ष्य शामिल हैं।

ऐसे में मानवता को ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में एक ईमानदार पहल की जरूरत है। यह हकीकत है कि वर्ष 1850 में वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड रखे जाने की शुरुआत के बाद से पिछले 12 साल सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चिंता जतायी है कि ग्यारह साल पहले हुए पेरिस समझौते का यह लक्ष्य कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए, अब हासिल न होगा। तभी 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' जैसे सम्मेलनों की सार्थकता को लेकर आलोचना होती है। विश्व समुदाय का निराश होना स्वाभाविक है क्योंकि पिछले दशकों में इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। तमाम सरकारें इस मुद्दे पर उदासीन नजर आती हैं। लेकिन इसके बावजूद बढ़ते तापमान और ग्रीनहाउस गैसों के भारी उत्सर्जन से निपटने के लिये ऐसे आयोजनों के जरिये गंभीर चर्चा करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिये बेहद जरूरी है कि वे अपने अलग-अलग और जटिल हितों के बीच उन उपायों को लागू करें, जिनको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

# कैंसर की दवाओं को सस्ती बनाने की प्रक्रिया और मरीजों को प्राथमिकता

■ जगत प्रकाश नड्डा



कैंसर' शब्द पल भर में ही किसी परिवार की जिंदगी बदल देता है। इस बीमारी की पहचान होने के बाद, मरीजों व उनके परिजनों को इलाज, आर्थिक मामलों और भविष्य से जुड़े कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कई परिवारों के लिए तो दवाओं का खर्च एक ऐसे समय में अतिरिक्त बोझ बन जाता है, जब सारे संसाधन मरीज को स्वस्थ करने में लगाए जाने चाहिए। एक करुणामयी स्वास्थ्य प्रणाली को सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली आर्थिक तंगी का भी समाधान निकालना चाहिए।

इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाकर 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के 'ट्रेड मार्जिन' को तर्कसंगत बना दिया है। इस उपाय के तहत, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 'ट्रेड मार्जिन' को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है और ये संशोधित कीमतें 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है- मरीज द्वारा चुकायी जाने वाली कीमत में अत्यधिक 'मार्क-अप' के बजाय वितरण संबंधी मार्जिन का उचित व तर्कसंगत समावेश होना चाहिए।

इस कदम के नतीजे दवा की दुकानों पर साफ नजर आने लगे हैं। कुल 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं से जुड़े 1,366 उत्पादों के लिए संशोधित एमआरपी की सूचना दी है। इनमें से प्रत्येक 5 में से 4 से अधिक उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। इन दवाओं में से लगभग आधे की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और कुछ दवाएं तो अब पहले की तुलना में 96 प्रतिशत से भी कम कीमत पर मिल रही हैं। कीमोथेरेपी के कई दौर का खर्च उठाने वाले परिवार के लिए, इस कदम से इलाज के मासिक बिलों में काफी अंतर आ जाता है। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर, मरीजों एवं उनके परिवारों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। यह वो रकम है जो अत्यधिक 'ट्रेड मार्जिन' में खप जाने के बजाय उनके घरेलू बजट में ही बनी रहेगी। यह निर्णय पिछले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। वर्ष 2019 में, एनपीपीए ने 'ट्रेड मार्जिन के युक्तिकरण' (टीएमआर) की कवायद के तहत एक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कैंसर की गैर-अनुसूचित श्रेणी की 42 दवाएं शामिल थीं। इससे 526 ब्रांडों की एमआरपी में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। अब इसी प्रक्रिया को 137 दवाओं की एक बड़ी सूची तक बढ़ाया जा रहा है। इन दवाओं की पहचान एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस विशेषज्ञ समिति में प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट), चिकित्सा विशेषज्ञ, अस्पताल विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा।



एक न्यायसंगत स्वास्थ्य व्यवस्था में दवाओं का किफायती होना जरूरी है। खासकर, भारत जैसे देश में। बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद अगर किसी दवा को बहुत महंगी होने के कारण खरीदना संभव न हो पाए, तो वह मरीज के किसी काम की नहीं है। एनपीपीए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत जारी 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013' के जरिए दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। जहां वह 'आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची' में शामिल जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमतें (सीलिंग प्राइस) निर्धारित करता है, वहीं गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों में हर वर्ष होने वाली बढ़ोतरी पर नजर भी रखता है। हालांकि, बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत और ग्राहक द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर बहुत अधिक था। इनमें कैंसर की वैसी दवाएं भी शामिल थीं, जिनकी खुराकें इलाज के दौरान अक्सर कई बार और बार-बार लेने की जरूरत पड़ती है। व्यापार श्रृंखला (ट्रेड चैनल) में बहुत अधिक मार्जिन और इलाज के भारी खर्च को देखते हुए, सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठाया है और मार्जिन को एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।

सरकार इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी ध्यान दे रही है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को टीएमआर का पूरा लाभ मिल सके। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित कीमतें हर फार्मेसी और अस्पताल तक पहुंचें। साथ ही, सभी फार्मेसियों और अस्पतालों को इन कीमतों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करना होगा और इनका सख्ती से पालन करना होगा। मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोग एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप पर इन संशोधित कीमतों को देख सकते हैं। अगर कोई फार्मेसी या अस्पताल निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलता है, तो वे इसकी शिकायत सरकार से कर सकते हैं।

टीएमआर की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से चल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक बदलाव का एक हिस्सा है। इस सरकार ने स्वास्थ्य को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, उत्पादकता और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में देखा है। खासकर, समाज के सबसे गरीब तबके के लिए। 'आयुष्मान भारत' ने कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल की सुविधाओं की सुलभता को आसान बना दिया है। सरकार ने कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और समय पर इलाज के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी-एनसीडी) के तहत, 500 से अधिक 'डे-केयर कैंसर सेंटर' स्थापित किए गए हैं ताकि कीमोथेरेपी तथा कैंसर संबंधी अन्य डे-केयर सेवाएं समय पर मिल सकें। 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कैंसर की आम बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता चल जाता है। तृतीयक स्तर की देखभाल (टर्शियरी केयर) को मजबूत करने हेतु, टाटा मेमोरियल सेंटर ने कैंसर की व्यापक देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सभी 22 नए एम्स में भी जांच, चिकित्सा और सर्जरी की सुविधाएं सहित कैंसर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' किफायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सरकार ने जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं को 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अमृत' फार्मेसियां भी स्थापित की हैं। इलाज के खर्च को और कम करने के इरादे से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से जुड़ी 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) से पूरी तरह छूट दी गई है।

**इस पेज में प्रकाशित लेख लेखक के उनके निजी विचार हैं।**

## प्रेरक प्रसंग

### वचन का प्रभाव

परम विरक्त संत स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज पैदल भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंच गए। वहां सुबह-शाम गंगा स्नान करते और दिन भर साधना में लगे रहते। गांव के बुजुर्गों को पता चला कि मंदिर में एक संत आया हुआ है और वह तीन दिनों से निराहार है। एक बुजुर्ग स्वामी जी के पास पहुंचा और उसने कहा, 'महाराज जी, आज आप हमारे यहां भोजन करने की कृपा करें।'

स्वामी जी ने उत्तर दिया, 'हम उसी के घर में भोजन ग्रहण करते हैं, जिस घर का एक भी सदस्य तंबाकू, शराब तथा मांस का सेवन न करता हो।' ज्यादातर परिवार मांस-मदिरा का सेवन नहीं करते थे, लेकिन हुक्का-बीड़ी का चलन तो घर-घर था। गांव का एक भी घर ऐसा नहीं निकला जिसके यहां बना भोजन स्वामी जी ग्रहण कर पाते। स्वामी जी हफ्ताभर बिना भोजन के रहे। 8वें दिन गांव के बुजुर्गों ने बैठक की। उनके मुखिया ने कहा कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है, जिसका एक भी सदस्य नशा न करता हो। कितनी शर्म की बात है कि एक संत कई दिनों से भूखा है। इसके बाद एक-एक करके कुछ बुजुर्ग उठे और उन्होंने संकल्प लिया कि आज से वे हुक्का-बीड़ी नहीं पिएंगे। कुछ ने शराब और मांस छोड़ने का संकल्प लिया। उसी दिन शाम को कुछ लोग स्वामी जी के पास पहुंचे। वे हुक्के और शराब की बोतलें भी अपने साथ ले गए। इन सभी ने हाथ में गंगाजल लेकर मांस-मदिरा और तंबाकू का सेवन न करने की शपथ ली। तब स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए एक घर की भिक्षा ग्रहण की।

## धर्म-कर्म

### अक्षय नवमी पर आंवला पेड़ की पूजा

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ आंवले के पेड़ की आराधना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर किए गए दान, जप, तप और पूजा का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसी वजह से इसे अक्षय नवमी कहा गया है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना से व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में अक्षय नवमी कब है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में अक्षय नवमी 18 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 6 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी और 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 18 नवंबर को ही अक्षय नवमी का व्रत और पूजन किया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा और दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। अक्षय नवमी को आंवला नवमी कहने के पीछे आंवले के पेड़ का धार्मिक महत्व जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए श्रद्धालु पेड़ की पूजा करके श्रीहरि का आशीर्वाद मांगते हैं। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और कार्तिक मास में इसकी पूजा विशेष फलदायी बताई गई है। इस दिन पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनने और भोजन करने की भी परंपरा है।

## आंचलिक

# सिविल लाइन वार्ड से एसएलआरएम सेंटर हटाने की मांग पर कांग्रेस का चक्काजाम

### महापौर जनता की परेशानी छोड़ प्रचार और फोटो सेशन में व्यस्त : सुशील मौर्य

समवेत शिखर संवाददाता

**जगदलपुर।** शहर के सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 07 में संचालित एसएलआरएम सेंटर अब स्थानीय रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सेंटर से निकलने वाली असहनीय दुर्गंध, कचरे का बढ़ता अंबार, गंदगी और मक्खी-मच्छरों के प्रकोप से परेशान वार्डवासियों की शिकायतों पर महीनों बाद भी कार्रवाई नहीं होने से मामला गरमा गया है। इसी समस्या को लेकर शुक्रवार को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष सुशील मौर्य की उपस्थिति में वार्ड पार्षद संध्या महंती मरकाम, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी एवं स्थानीय नागरिकों के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षद दल ने भंगाराम चौक पर धरना-प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिविल लाइन वार्ड के रिहायशी इलाके से एसएलआरएम सेंटर को तत्काल हटाने की मांग उठाई।



प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से संचालित कचरा प्रबंधन केंद्र ही यदि आसपास रहने वाले नागरिकों के लिए दुर्गंध, गंदगी और बीमारियों की आशंका का कारण बन जाए, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एसएलआरएम सेंटर के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र, पीडब्ल्यूडी की आवासीय कॉलोनी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की राशन दुकान संचालित है। ऐसे में छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और रोजाना राशन लेने पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम में भाजपा की सत्ता और महापौर को आम जनता की बुनियादी समस्याओं से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। शहरवासी गंदगी और असहनीय दुर्गंध के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं, लेकिन महापौर और निगम प्रशासन जनता की परेशानी दूर करने के बजाय अपनी उपलब्धियां गिनाने, विज्ञापन, बड़े आयोजनों और फोटो सेशन में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल बैनर, पोस्टर और विज्ञापनों में दिखाई देने से नहीं आती, बल्कि प्रत्येक वार्ड के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने से आती है।

मौर्य ने कहा कि सिविल लाइन जैसे रिहायशी इलाके में कचरे का अंबार और दुर्गंध के बीच बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का रहना गंभीर चिंता का विषय है। जिस स्थान पर छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में शिक्षा और पोषण प्राप्त करने आते हैं, वहां गंदगी और मक्खी-मच्छरों का वातावरण बना रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के स्वास्थ्य से बढ़कर कोई आयोजन और राजनीतिक प्रचार नहीं हो सकता। कांग्रेस वार्डवासियों की इस जायज मांग के साथ खड़ी है और जब तक उन्हें स्थायी राहत नहीं मिलती, तब तक उनकी आवाज उठाती रहेगी। वार्ड पार्षद संध्या महंती मरकाम ने कहा कि सिविल लाइन वार्ड के रहवासी लंबे समय से एसएलआरएम सेंटर से निकलने वाली दुर्गंध और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस संबंध में 29 जुलाई 2026 को ही वार्डवासियों की ओर से नगर निगम आयुक्त को लिखित आवेदन सौंपकर समस्या से अवगत करा दिया गया था। आवेदन में दुर्गंध, कचरे के ढेर, मक्खियों और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप सहित नागरिकों को हो रही परेशानियों का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

उन्होंने विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि एसएलआरएम सेंटर के आसपास फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण वहां आने वाले छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन यहां हालात ऐसे हैं कि उनके लिए बैठना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं सेंटर के सामने स्थित पीडब्ल्यूडी आवासीय कॉलोनी के रहवासी भी लगातार दुर्गंध से परेशान हैं।

## आज का इतिहास

- 1681 : ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक अलग रियासत बनाने की घोषणा की।
- 1889 : स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म।
- 1922 : ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा की शुरूआत की।
- 1935 : आधुनिक जॉर्डन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शाह हुसैन का जन्म।
- 1948 : ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स का जन्म। वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के सबसे बड़े पुत्र हैं।
- 1955 : कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन।
- 1964 : आज के दिन को 'बाल दिवस' के रूप में मनाने का आधिकारिक ऐलान।
- 1969 : अपोलो-12 को प्रक्षेपित किया गया, जो तीन अंतरिक्षयात्रियों को लेकर आकाश की अनंत गहराइयों को पार करते हुए चंद्रमा पर पहुंचा।

# कम धान उत्पादन होने पर भी किसानों को कृषक उन्नति योजनांतर्गत मिलेगा 21 क्विंटल के मान से लाभ
## किसान अमेश यादव ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

समवेत शिखर संवाददाता

**दंतेवाड़ा।** प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हित में लिए जा रहे निर्णयों से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। शासन की किसान हितैषी योजनाओं और धान खरीदी की सुविधाओं से किसानों में उत्साह का माहौल है।

इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के बालूद ग्राम के किसान श्री अमेश यादव ने शासन की कृषक उन्नति योजना से मिलने वाले लाभ पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसान अमेश यादव ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें शासन की कृषक उन्नति योजना के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से लाभ दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी किसान का वास्तविक धान उत्पादन 5 या 10 क्विंटल ही होता है, तब भी निर्धारित पात्रता एवं योजना के प्रावधानों के अनुसार 21 क्विंटल के मान से लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। इसके तहत 13,849 रुपये की राशि मिलने की बात बताई गई है। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शासन द्वारा तुहर टोकन ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे ही अपने धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को टोकन कटवाने के लिए बार-बार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। अमेश यादव ने कहा कि शासन की किसान हितैषी पहल से किसानों को काफी राहत मिल रही है। कम धान उत्पादन होने की स्थिति में भी निर्धारित प्रावधानों के तहत लाभ मिलने की जानकारी से किसान खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

प्रथम पेज का शेष

## गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओ...

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं : मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

**किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी :** मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

**प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि :** मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

**महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल :** मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

## ►► न्यूज ब्रीफ

### प्रति एकड़ 13,839 का निर्णय किसान हित में महत्वपूर्ण पहल : मंत्री गजेन्द्र यादव



**दुर्ग।** मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण और राहतकारी पहल बताया है। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की मेहनत, उनकी जरूरतों और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब किसान यदि कम उत्पादन के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें सत्यापित धान के रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पहले कम उत्पादन होने की स्थिति में किसानों को निर्धारित मात्रा के अनुपात में ही सहायता मिल पाती थी। अब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि कम उपज के कारण उन्हें आर्थिक सहायता से वंचित न होना पड़े। यह निर्णय विशेषकर उन किसानों के लिए लाभकारी होगा, जहां प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धान का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान कल्याण की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

### 15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, पहले दिन 192 किसान बेचेंगे 7,250 क्विंटल धान

**कवर्धा।** खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से प्रदेश सहित कबीरधाम जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ होने जा रहा है। धान खरीदी को लेकर जिले के किसानों में उत्साह का माहौल है। किसान अपनी मेहनत से उपजाए धान को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि किसानों को उपज विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। धान खरीदी के पहले दिन के लिए जिले के 192 किसानों ने टोकन कटाया है, जिनके द्वारा कुल 7,250 क्विंटल धान का विक्रय किया जाएगा। वहीं, अब तक जिले के 137 उपार्जन केंद्रों में 7,266 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से अपना टोकन कटाया है। इन किसानों द्वारा कुल 3,84,202.70 क्विंटल धान का विक्रय किया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। किसानों को पारदर्शी, सुगम और व्यवस्थित तरीके से धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कबीरधाम जिले में इस खरीफविपणन वर्ष में कुल 1 लाख 31 हजार 265 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है।

# 16 नवंबर को कला मंदिर ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस

### कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

समवेत शिखर संवाददाता



**दुर्ग।** जनजातीय गौरव, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने जिले में 16 नवंबर को जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। कार्यक्रम महात्मा गांधी कला मंदिर ऑडिटोरियम, सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम का सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह को सम्पूर्ण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार गुप्ता एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अविनाश श्रीवास को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों को अलग-अलग दायित्व सौंपे गए हैं। पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल अधिकारी को अतिथियों के आमंत्रण, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग/ धमधा/ पाटन/भिलाई-3 को स्थानीय जनजाति वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके वंशजो की सूची उपलब्ध करना और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण, लोक निर्माण विभाग को बैठक व्यवस्था, मंच सज्जा एवं आवश्यक सुविधाओं की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था के साथ जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर, प्रयास विद्यालय, विज्ञान विकास केन्द्र एवं छात्रावासों/प्रमुख स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य एवं सिकलसेल जांच शिविर आयोजित करना और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरण करेगा।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जनजातीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में साफ सफाई, वृक्षारोपण एवं चित्रकला और जनजातीय संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी। उद्यानिकी विभाग बुके एवं फूल माला की व्यवस्था, परिवहन विभाग बस/वाहन की ईंधन की व्यवस्था, शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभावान बच्चों का सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, निबंध लेखन, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

# छठ महापर्व की तैयारियों का विधायक ललित चंद्राकर ने लिया जायजा

### मरोदा टैंक, नेवई डेम और मां कल्याणी शीतला मंदिर तालाब पहुंचकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

समवेत शिखर संवाददाता

**दुर्ग।** सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने छठ पर्व के मद्देनजर मां कल्याणी शीतला मंदिर तालाब, मरोदा टैंक एवं नेवई डेम का निरीक्षण कर घाटों पर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विधायक ने छठ घाटों पर साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, अस्थायी शौचालय, बैरिकेडिंग, पार्किंग, आवागमन के मार्ग तथा सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि छठ महापर्व आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अस्ताचलगामी एवं उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से घाटों पर पानी की गुणवत्ता की जांच, गहरे पानी वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, गोताखोरों एवं पुलिस बल की तैनाती तथा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था, घाटों की नियमित सफाई और कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न छठ पूजा समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। विधायक ललित चंद्राकर ने समस्त छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि भगवान भास्कर की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य का संचार हो।

# धान खरीदी नीति में बदलाव किसानों के हित में बड़ा फैसला : शीला टाकेश सिन्हा

### साय सरकार के निर्णय से किसानों को मिलेगा पूरा लाभ भाजपा सरकार किसान हितैषी

समवेत शिखर संवाददाता



**राजनांदगांव।** छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार किसानों के हितों और उनकी आर्थिक समृद्धि को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 15 नवंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी में किसानों को उनकी वास्तविक उपज के अनुरूप निर्धारित प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि का लाभ दिए जाने के निर्णय से प्रदेश के किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल है। इस फैसले को किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताते हुए जिला पंचायत सभापति श्रीमती शीला टाकेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

श्रीमती सिन्हा ने कहा कि भाजपा सरकार ने धान खरीदी नीति में बदलाव कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार का यह निर्णय उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा, जिन्होंने मेहनत और लगन से अपनी फसल तैयार की है। अब किसानों को उनकी उपज के अनुरूप निर्धारित व्यवस्था के तहत लाभ मिल सकेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती-किसानी के प्रति उनका भरोसा और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केवल किसानों ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखकर योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार की नीतियां सराहनीय हैं। श्रीमति सिन्हा ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा धान खरीदी केंद्रों और समितियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी किसानों के लिए काफी राहत भरा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के केंद्रों तक जाने की परेशानी कम हुई है। खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ने से धान विक्रय की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हुई है और किसानों को समय तथा परिवहन खर्च की बचत भी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को समझते हुए लगातार उनके समाधान की दिशा में काम कर रही है।

# पोटिया में घर-घर पीलिया का डर, आखिर कब जागेगा नगर निगम, अरुण वोरा ने किया दौरा

समवेत शिखर संवाददाता



**दुर्ग।** शहर के पोटियाकला क्षेत्र में पीलिया के 15 मरीज सामने आने से शासन-प्रशासन की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।7 से 12 नवंबर के बीच सामने आए इन मामलों ने क्षेत्र में पेयजल की शुद्धता और स्वच्छता की स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने पोटियाकला का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।आबादीपारा के स्थानीय निवासी राकेश साहू के परिवार के छह सदस्यों के पीलिया से प्रभावित है।अब तक करीब 15 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें सात मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 6-7 बच्चे संक्रमण से प्रभावित हैं।क्षेत्र में भय और असमंजस का माहौल है।कई मरीज जिला अस्पताल में उपचार कराने से कतरा रहे हैं। उन्हें वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं और उपचार को लेकर आशंकाएं हैं।बजाय झाड़-फूंक का सहारा ले रहे हैं।बच्चे भी अस्पताल जाने को तैयार नहीं हैं।

अब तक किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं जानने की पहल नहीं की।अरुण वोरा ने पीलिया से प्रभावित मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। पीड़ित परिवारों के बीच मौजूदगी के दौरान ही अरुण वोरा ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें क्षेत्र की गंभीर स्थिति से अवगत कराया तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

# साय सरकार का फैसला किसानों के लिए बड़ी सौगात : अशोक देवांगन

समवेत शिखर संवाददाता



**राजनांदगांव।** भारतीय जनता पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक देवांगन मामा ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी सरकार है। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। 15 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में अब किसानों को उनकी वास्तविक धान बिक्री के साथ-साथ निर्धारित पात्र रकबे के आधार पर भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।

श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान उन्नति योजना के तहत किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार जिन पात्र किसानों ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचा है उन्हें भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी इनपुट सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी किसानों को कम धान बेचने के कारण सहायता राशि में कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 तक की इनपुट सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जिले सहित पूरे प्रदेश के किसानों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। यह निर्णय उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा जिनकी फसल का उत्पादन मौसम, प्राकृतिक परिस्थितियों अथवा अन्य कारणों से कम हुआ है। अब ऐसे किसानों को भी निर्धारित पात्र कृषि रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती-किसानी के कार्यों में उन्हें संबल मिलेगा। अशोक देवांगन ने कहा कि भाजपा सरकार केवल धान खरीदी तक ही सीमित नहीं है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत का बोझ कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार फैसले ले रही है।

### जिले में इस वर्ष 123 धान उपार्जन केंद्रों में होगी खरीदी, 21 नवीन उपार्जन केंद्रों की हुई वृद्धि, 39 केंद्र संवेदनशील घोषित

**दुर्ग।** खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में समर्थन मूल्य पर 15 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। धान खरीदी संबंधी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वर्ष जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या, पंजीकृत किसानों और धान के रकबे में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जिले में 102 धान उपार्जन केंद्र संचालित थे, जिनकी संख्या इस वर्ष बढ़कर 123 हो गई है। इस तरह जिले में 21 नवीन धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। नवीन उपार्जन केंद्रों में सुरडुंग, सिल्ली, नंदवाय, अरसी, असोगा, अरसनारा, धौराभाठा, धनोरा, गनियारी, खजरी, सिकोला, जरवाय, पेंड्री, मेड़ेसरा, बोरवाय, अरमरीखुर्द, ढौर, कातरो, सेमरिया, मलपुरीकला एवं महकाखुर्द शामिल हैं। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में सुचारू एवं व्यवस्थित धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिले में 118 सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 39 धान उपार्जन केंद्रों को संवेदनशील केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया की सतत निगरानी एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

# एक माह से मांगों पर अड़े पटवारियों ने कहा- हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पूरी करें मांग

समवेत शिखर संवाददाता




**साजा।** राजस्व व्यवस्था की जमीनी जिम्मेदारी संभालने वाले पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। समयमान वेतन, पदोन्नति और पीवी ऐप की खामियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच बेमेतरा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार पटवारियों को निलंबित कर दिया है। इससे पटवारी संघ के आंदोलन के बीच प्रशासनिक सख्ती का नया अध्याय शुरू हो गया है।

बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से जारी कार्रवाई के अनुसार बेमेतरा तहसील के बोधीराम निषाद, बेरला तहसील के लोकेश रात्रे, थान खम्हरिया तहसील के तारनदास पाटले और नांदघाट तहसील के दिलेश्वर साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बेमेतरा जिले की चारों अनुविभागों की तहसीलों में कुल 150 पटवारी पदस्थ हैं। नियमित पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण राजस्व व्यवस्था का कामकाज प्रभावित हो रहा है। फिलहाल प्रशिक्षु पटवारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रशासन ने पहले हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

साजा तहसील में कुल 35 पटवारी पदस्थ हैं। प्रशिक्षु पटवारियों को छोड़कर शेष पटवारी हड़ताल में शामिल हैं। ऐसे में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थान खम्हरिया तहसील के पटवारी तरनदास पाटले का निलंबन साजा अनुविभाग में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बेमेतरा जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष निर्जल कुमार डिंडोरे के अनुसार, पटवारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को शासन के समक्ष उठाते आ रहे हैं। समयमान वेतन का लाभ, पदोन्नति के अवसर, पीवी ऐप में तकनीकी एवं व्यावहारिक सुधार सहित अन्य मांगों पर अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं हुआ है। साजा तहसील पटवारी संघ के अध्यक्ष सुंदरलाल धृतलहरे का कहना है कि पटवारी राजस्व प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण मैदानी कड़ी हैं।

# बासिनझोरी से केजेदाह तक 3.92 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पक्की सड़क

### उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से वनांचल क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता

समवेत शिखर संवाददाता

**कवर्धा।** बारिश होते ही कीचड़ से पट जाने वाला कच्चा रास्ता अब वनांचल के ग्रामीणों की परेशानी नहीं बनेगा। सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बासिनझोरी से केजेदाह तक 3 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 2.7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र के 1500 से अधिक ग्रामीणों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए यह निर्माण राहत लेकर आया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और गांवों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के वनांचल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। सड़कों का निर्माण केवल आवागमन का साधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के जीवन में सुविधा, विकास और नई संभावनाओं के द्वार खोलने का माध्यम भी बन रहा है।

**किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को मिलेगी सुविधा :** सड़क बनने से किसानों को अपनी उपज बाजार और धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने में आसानी होगी। विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज आने-जाने और व्यापारियों को सामान के परिवहन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीणों को अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सहूलियत होगी। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी आसान होगा।

**ग्रामीणों ने जताया आभार, वर्षों पुरानी समस्या होगी दूर :** ग्राम बासिनझोरी और आसपास के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पर खुशी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्चे रास्ते के कारण उन्हें लंबे समय से परेशानी हो रही थी। विशेषकर बारिश के दिनों में कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता था। पक्की सड़क बनने से यह समस्या दूर होगी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं उप मुख्यमंत्री तथा कवर्धा विधायक विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है।



**सड़क से वनांचल के गांवों का बढ़ेगा जुड़ाव :** बासिनझोरी से केजेदाह तक सड़क निर्माण से वनांचल क्षेत्र के गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क मजबूत होगा। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। बेहतर आवागमन से क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। यह सड़क 1500 से अधिक ग्रामीणों के लिए विकास और सुविधा का नया रास्ता खोलेगी।

### कलेक्टर ने निर्माणाधीन महतारी सदन का किया निरीक्षण

**कवर्धा।** कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम चारभाठा में निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि महतारी सदन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि महतारी सदन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र साबित होगा। इसके निर्माण से महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसे समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

### प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रोशन हो रहे छत्तीसगढ़ के घर, बिजली बिल से मिल रही बड़ी राहत

**राजनांदगांव।** छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम परिवारों के लिए आर्थिक बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया जरिया बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर अब घर-घर दिखाई देने लगा है। कभी हर महीने हजारों रूपए बिजली बिल चुकाने वाले परिवार अब अपने घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल से बिजली पैदा कर रहे हैं।

**OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL BHOPALPATNAM, DIST-BIJAPUR (CG)**

**E-Procurement Tender Notice (2nd Call)**

SYSTEM TENDER NO/ 203582/NIT NO: 587

BHOPALPATNAM, dated 04.11.2026

Online bids in three envelop system are invited for the following construction works/up to date 20-11-2026 at 17:00 Hours

| System tender No. | Description | PAC (Rs. In LAKHS) |
|---|---|---|
| 203582 | Construction Of RCC Drain At Ward No. 04,07,09 & 10 of Bhopalpatnam, Chhattisgarh (Total 05 Works) | 25.18 |

The details can be downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal **http://eproc.cgstate.gov.in and https://uad.cg.gov.in/**From 05-11-2026 at 17:30 Hours. (IST) onwards.

For more details on the tender and bidding process please visit the above mentioned portal.

**CHIEF MUNICIPAL OFFICER**
**MUNICIPAL COUNCIL BHOPALPATNAM (CG)**

# अधिकारी जनता की सुविधाओं के लिए कार्य करें : बघेल

## प्रभारी मंत्री बघेल ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

समवेत शिखर संवाददाता



**महासमुंद।** प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चार घंटे चली बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचानेए विकास कार्यों को समय.सीमा में पूरा करने तथा विभागीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू, जनप्रतिनिधिगण एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने मैदानी स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण करने तथा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026.27 के लिए धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओंए पारदर्शी प्रक्रिया तथा किसानों की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पिछले वर्ष धान खरीदी के दौरान सामने आई अनियमितताओं एवं उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।

प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास करें। विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय.सीमा में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयीन समीक्षा तक सीमित न रहेंए बल्कि समय.समय पर मैदानी क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लें।

## जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कल से

**एक लाख 62 हजार से अधिक किसान पंजीकृत**

**महासमुंद।** खरीफ विपणन वर्ष 2026.27 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छग शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में प्रारंभ होने जा रहा है। जिले में धान खरीदी को सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शासन के मंशानुरूप व्यापक तैयारियां की गई हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी 202 धान खरीदी केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिला एवं अनुविभाग स्तरीय कुल 75 अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी अपने निर्धारित खरीदी केंद्रों में धान उपार्जन की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखेंगे तथा खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। साथ ही जिले के 55 संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील उपार्जन केन्द्रों में सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान खरीदी एवं मॉनिटरिंग हेतु जिले के संवेदनशील उपार्जन केंद्रों में 55 नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं प्रत्येक उपार्जन केन्द्र के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रणए सतत निगरानी, धान की गुणवत्ता, बारदानों की उपलब्धता, धान का भण्डारण एवं परिवहन, किसानों को धान विक्रय करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में धान उपार्जन प्रक्रिया की समाप्ति तक उपार्जन केंद्र स्तर पर 202 अधिकारियों.कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। धान खरीदी अवधि के दौरान ओड़िशा राज्य से अवैध धान की आवक एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए जिले में 15 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। इन जांच चैकियों को 1 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। यहां राजस्व विभाग, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग एवं जिला सेनानी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जांच दलों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में धान के अवैध परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस वर्ष कुल 1 लाख 62 हजार 566 किसानों का पंजीयन किया गया है। जिले में 159 सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित 202 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2026.27 के लिए जिले में 2,35,394,44 हेक्टेयर पंजीकृत रकबे के अंतर्गत कुल 11,17,884 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## न्यूज ब्रीफ

### जानलेवा हमले में घायल दमाद ने तोड़ा अस्पताल में दम



**महासमुंद।** पुराना घरेलू विवाद का खूनी खेल सामने आया। ससुराल पहुंचे दामाद पर लाठी,डंडे, रॉड व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर संघातिक चोंटे पहुंचाई। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शहर के नयापारा में दीपक ठाकुर अपने कार क्रमांक सीजी 06 एचई 8881 से अपने ससुराल पहुंचा था जहां ससुराल पक्ष के साथ उनका जमकर विवाद हुआ और विवाद खूनी खेल में बदल गया। करीब 20-25 मिनट तक दीपक ठाकुर की बेरहमी से पिटाई की गई जहां वह अचेत होकर पड़ा रहा। घायल दीपक के परिचितों को जानकारी मिलने पर 112 की मदद ली गई और उसे नगर के एक नीजि अस्पताल ले जाया गया जहां गंभीर स्थिति देखते हुए रामकृष्ण अस्पताल रायपुर रिफर किया गया वहां जीवन-मृत्यु के बीच वेंटीलेटर में रखा गया था। 12-13 नवंबर की दरम्यानी रात उसकी मौत हो गई। मामले में सिटी कोतवाली ने रमनटोला निवासी सुनीता सिंह ठाकुर पति स्व. रज्जू सिंह ठाकुर की शिकातय पर नयापारा निवासी दूजराम सेन, लक्ष्मण सेन, मनीष सेन, कुमकुम सेन व अन्य के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। प्रार्थिया ने शिकायत की है कि उसके लड़के दीपक ठाकुर के साथ आरोपियों ने प्राणघातक हमला किया है। लोगों का कहना है कि मृतक ने प्रेम विवाह किया था। कुछ विवाद पर उसकी पत्नी मायके चली गई थी और वही कुछ दिनों से रह रही थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक बिलासपुर का रहने वाला है जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। नगर के रमनटोला वह निवासरत था।

### कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13839 रुपए

**महासमुंद।** छग शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026.27 में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को रकबे के अनुसार प्रति एकड़ 13ए839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि लागत कम करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खरीफवर्ष 2026.27 में कुल 159 समितियों के माध्यम से एक लाख 62 हजार 566 किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन किया गया है। जिसमें किसानों के भूमि का कुल रकबा 235394,44 हेक्टेयर है तथा किसानों के धान का रकबा 216503,22 हेक्टेयर है। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026.27 में धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, एग्रीस्टैक में पंजीकृत हैं तथा उनके द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा चुका है। धान बीज उत्पादन में भाग लेने वाले किसान भी योजना के लिए पात्र होंगे। हालांकि पंजीकृत ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एवं शाला विकास समिति जैसी संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

## बातचीत से नहीं, धमकी और अनैतिक कार्रवाइयों से शासन चला रही सरकार : विनोद चंद्राकर

समवेत शिखर संवाददाता



**महासमुंद।** सरकार बातचीत के जगह धमकी और डर दिखाकर शासन चलाना चाहती है, जिसका नतीजा सामने है। तहसीलें खाली हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं और किसान तहसील के चक्कर काट रहा है। पूर्व संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है। एक तरफ पटवारियों पर अनैतिक कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारियों की हड़ताल से राजस्व, तहसील और किसानों के जो काम अटक रहे हैं, उस पर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाने को तैयार नहीं है।

श्री चंद्राकर ने कहा कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक महीना हो गया। 13 अक्टूबर से शुरू हुई यह हड़ताल आज पूरे प्रदेश की व्यवस्था को जाम कर चुकी है। सरकार ने इस दौरान 60 से अधिक पटवारियों को निलंबित कर दिया और 1000 से ज्यादा को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस थमा दिया। सोचिए जो पटवारी गांव की जमीन का हिसाब रखता है, उसी को सरकार अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। वेतन विसंगति दूर करो, पदोन्नति दो, पीवी ऐप के बोझ से मुक्ति दोए ये तीन छोटी सी मांगें थीं। सरकार ने मांगें सुनीं नहीं, उल्टा फाइलों में सस्पेंशन के आदेश लिख दिए। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी अवकाश पर जाने को मजबूर हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों से पूरा अमला परेशान है।

## जनजातीय बहुल जिलों में मनाया जा रहा है गौरव सप्ताह : पुजारी

### जिला स्तरीय आयोजन 16 को, आज स्मारकों और प्रतिमाओं की साफ-सफाई

समवेत शिखर संवाददाता



**महासमुंद।** धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151 वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सिलसिले में 11 से 18 नवंबर तक देश के प्रत्येक जनजातीय बहुल जिले विधानसभा और मंडल में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा।

इस कार्यक्रम के जरिए जनजातीय समाज की जीवन में आए परिवर्तन और विपक्ष के भ्रम के सच्चाई को सामने रखा जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए जनजाति गौरव दिवस आयोजन समिति के जिला प्रभारी बिंद्रा नवागढ़ के पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन के निर्देश पर 239 जनजातीय जिलों और 568 जनजातीय विधानसभा क्षेत्रों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई और दीपोत्सव तथा 15 को जिला स्तर पर प्रतिमा और हर मंडल में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण किया जएगा। 16,17,18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जनजाति छात्रावास संपर्क अभियान के माध्यम से छात्रावासों में जाकर जनजाति विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, जनजाति गौरव दिवस के महत्व और जनजाति कल्याण योजनाओं से अवगत कराएंगे। भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। उन्होने बताया कि सिद्धोकान्हू, चांदभैरव, संथालहूल, शहीद वीरनारायण सिंह, तेलंगा खरिड़ा, बुद्धभगत, रानीदुर्गावती जैसे वीरों ने देश के लिए सर्वस्त्र न्यौछावर किया किंतु विपक्ष ने कभी भी इन्हें याद नही किया और इतिहास को छिपाए रखा। इस दौरान पूर्व विधायक प्रीतम सिंह दीवान, जिलाध्यक्ष ऐतराम साहू, धरम दीवान, राधेश्याम ध्रुव, भुनेश्वर ध्रुव, कृष्ण कुमार ध्रुव, चंद्रशेखर ध्रुव आदि मौजूद थे।

## नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है मातर महोत्सव : निखिलकांत

समवेत शिखर संवाददाता



**महासमुंद।** सिरपुर क्षेत्र के ग्राम गुडरुडीह, फुसेराडीह, सुकुलबाय, परसाडीह, अछोला सहित बकमा व सोरिद के मातर महोत्सव तथा ग्राम गौरखेड़ा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू शामिल हुए। हर गांव में समाजजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

उन्होंने मातर महोत्सव में यादव समाजजनों की सांस्कृतिक परंपरा की प्रशंसा की। सभी स्थानों पर पूजा कर समाज की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मातर महोत्सव हमारी माटी की पहचान है। राउत नाचा, मातर की पूजा और गांव का एक साथ जुटनाए यही छत्तीसगढ़ की असली ताकत है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और नई पीढ़ी को संस्कार देता है। उन्होंने कहा कि यादव समाज ने अपनी परंपरा को पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ संभालकर रखा है, यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सभी गांवों में समाज के लोगों को महोत्सव की बधाई देते हुए सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना की। इसके बाद ग्राम गौरखेड़ा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पहुंचकर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। गौरखेड़ा के कबड्डी खिलाड़ियों को संबोधित कर उन्होंने बेहतर खेल प्रदर्शन व आपसी सौहार्द के साथ खेल गतिविधियों के आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कबड्डी सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह दिमाग, टीम वर्क और अनुशासन का खेल है। मैदान में जीत.हार से ज्यादा जरूरी है आपसी सम्मान और भाईचारा। उन्होंने युवाओं से कहा कि खेल को नशे और बुराई से दूर रहने का सबसे अच्छा माध्यम बनाएं। जो युवा खेल में आगे बढ़ता है, वह जीवन में भी कभी हार नहीं मानता। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि गांव में इस तरह के आयोजन युवाओं को सही दिशा देते हैं और गांव का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

## महासमुंद पुलिस की रायपुर में सूदखोरी पर बड़ी कार्रवाई

### आरोपी के कब्जे से अनेक लोगों के हस्ताक्षरित 160 कोरे चेक, 48 स्टाम, ऋण पुस्तिका बरामद

समवेत शिखर संवाददाता



**महासमुंद।** अवैध सूदखोरी, भयादोहन और जबरन वसूली के मामले में महासमुंद पुलिस ने रायपुर में जाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोवा डाल्फिन प्लाजा निवासी कुलदीप सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न व्यक्तियों के हस्ताक्षरित 160 कोरा चेक,48 कोरा स्टाम, 9 ऋण पुस्तिका, जमीन के कागजात जब्त किए है।

इसके अलावा आरोपी के कब्जे से 27 एटीएम, 17 बैंक पासबुक, ब्याज के लेनदेन संबंधी बहीखाता के अलावा 1 लाख 20 हजार रुपए नगद बरामद हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी कार्यालय में एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपी कुलदीप सिंह छाबड़ा के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उनके द्वारा ऋणजाल में फंसाकर लोगों से फार्मेटी के नाम पर कोरे चेक और स्टाम आदि रख लेता था बाद में चेक बाउंस कराकर ऋणियों को प्रताड़ित कर मनमाने धनराशि उगाही करता था। प्रारंभिक विवेचना में करीब 3 से 4 करोड़ का मामला सामने आया है। विवेचना के दौरान और भी जानकारी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि एसपी कार्यालय को बसना थाना क्षेत्र के बंसुलाडीपा निवासी विनोद चौहान ने शिकायत की थी कि गाड़ी बनवाने के लिए उन्होंने कुलदीप सिंह छाबड़ा से 42 हजार रुपए उधार लेकर अपने छोटे भाई पितांबर चौहान के खाते में डलवाये थे। उधार देते समय आरोपी ने औपचारिकता का बहाना बनाकर दोनों भाईयों से हस्ताक्षर कराकर खाली चेक, पासबुक, आधार कार्ड की प्रतियां अपने पास रखवा ली। इसके बाद आरोपी घर में आदमी भेजकर व फोन पर डराधमकाकर 8 माह में छोटे भाई से 40 हजार रुपए ले लिया। इतना ही नही घर के बर्तन, सोना-चांदी लिखवाकर 25 हजार रुपए नगद सहित मूल से अधिक राशि वसूल ली। इसके बाद भी आरोपी ने चेक वापस नही लौटाया बल्कि घर में घूसकर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। चेकों में मनमानी राशि भरकर न्यायालयों में प्रकरण लगाकर बर्बाद करने का भय दिखाया। प्रकरण की गंभीरता पर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो अनेक गरीब ऋणियों के हस्ताक्षरित चेक, स्टाम पेपर, बैंक पासबुक जब्त किए गए। बसना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 308 (2),296, 351 (2) तथा छग ऋणियों के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

## धान खरीदी केन्द्रों पर पारदर्शिता और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए निगरानी समितियों का गठन

### वास्तविक किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित करने कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

समवेत शिखर संवाददाता



**धमतरी।** खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जिले में 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में समिति स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में 5 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) का धान वास्तविक किसानों से ही खरीदा जाए। समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खरीदी केन्द्र में उपस्थित रहकर खरीदी कार्य की निगरानी करनी होगी। इस दौरान धान की सही तौल, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की प्रमाणिकता तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

**17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं होगा उपार्जित-** किसानों द्वारा लाए गए धान की नमी की जांच प्रतिदिन आर्द्रतामापी यंत्र से की जाएगी। शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान खरीदी योग्य नहीं होगा। इसी तरह निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने अथवा पुराना धान होने पर भी खरीदी नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में धान के तीन नमूने तैयार किए जाएंगे। इनमें से एक नमूना पावती सहित संबंधित किसान को वापस किया जाएगा तथा शेष दो नमूने परीक्षण के लिए समिति के पास सुरक्षित रखे जाएंगे।

**कोचियों और बिचौलियों पर रहेगी विशेष निगरानी-** धान खरीदी केन्द्रों पर कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से धान की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से धान विक्रय करने का प्रयास करता है, तो तत्काल प्रकरण दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को भी अपने प्रभार क्षेत्र के खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा धान विक्रय किए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

**किसानों की सुविधा और शिकायतों के निराकरण पर जोर-** खरीदी केन्द्रों में प्रतिदिन किसानों से खरीदे गए धान की मात्रा की कृषकवार सूची तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यह सूची एक सप्ताह तक प्रदर्शित रहेगी, ताकि खरीदी की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। निगरानी समितियों को स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही केन्द्रों में पर्याप्त नए एवं पुराने बारदानों का भंडारण, उनकी नियमित आपूर्ति तथा खरीदे गए धान के समयबद्ध परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक खरीदी केन्द्र के मुख्य द्वार पर शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की दर प्रतिदिन कपड़े के बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की पर्याप्त उपलब्धता और उनका नापतौल विभाग से सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। खरीदी केन्द्रों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयों को भेजनी होगी।

**अधिकारियों को नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी-** कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), खाद्य अधिकारी, उपायुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विपणन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों एवं नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

## समता कॉलोनी में राष्ट्रीय स्तर की प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी कल तक : चोपड़ा

### प्रदर्शनी में सजेंगे 30 से ज्यादा स्टॉल, दिखेगा वस्तुओं का संग्रह

समवेत शिखर संवाददाता



**महासमुंद।** छत्तीसगढ़ मुद्राशास्त्रीय एवं डाक टिकट संग्रह सोसायटी दक्षिण कौशल मुद्रा उत्सव समिति द्वारा 13 से 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी स्थित श्री रामनाथ भीमसेन भवन में तीन दिवसीय विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सोसायटी के सदस्य महासमुंद के राजा चोपड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रवेश नि:शुल्क होगा और यह सुबह 10.30 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में सिक्के, नोट, टोकन, पदक, डाक टिकट, प्राचीन वस्तुएं, सहायक उपकरण और विंटेज सामग्री सहित कई अनमोल संग्रह देखने को मिलेंगे। यह आयोजन कला और इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।

आयोजन समिति के सदस्य राजा चोपड़ा ने बताया कि इस आयोजन का प्रचार.प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, जिसके चलते देश के विभिन्न राज्यों से लोग इस प्रदर्शनी में शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी इतिहास, कला और संग्रह के शौकीनों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन रामनाथ भीमसेन भवन समता कॉलोनी में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर आयोजन में 30 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे।। प्रदर्शनी में मुंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी में पुराने नोट, सिक्के, टेलीफोन, मूर्ति, रत्न व विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलेगा। दक्षिण कौशल मुद्रा परिषद के सदस्य राजा चोपड़ा ने बताया कि शहर में इस तरह की प्रदर्शनी पहली बार देखने को मिलेगी। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग सुबह 10.30 से शाम 7 बजे आ सकते हैं। राजधानी रायपुर में 13 से 15 नवम्बर तक दक्षिण कोसल मुद्रा उत्सव प्रदर्शनी मे महासमुंद जिले से राजा चोपड़ा भी अपने संग्रह से पुराने नोट जिसमे फैंसी नंबर, त्रुटि पूर्ण नोट , अति दुर्लभ सिक्कों को प्रदर्शित करेंगे , समता कॉलोनी में 13 से 15 नवम्बर तक दक्षिण कोसल मुद्रा उत्सव आयोजन को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष कमल वैद्य, सचिव हेमंत अरोरा, संस्थापक सदस्य राजा चोपड़ा, हरिओम अग्रवाल सहित स्नेहल लुनिया, कमल अग्रवाल, धीरू सिंह, अनिल केशरवानी, अर्पित ताम्रकार एवं रितेश जैन सहित समिति के अन्य सदस्य सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। समिति के सदस्यों ने नगरवासियों, इतिहास एवं पुरानी वस्तुओं में रुचि रखने वाले लोगों तथा विद्यार्थियों से इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पहुंचकर दुर्लभ संग्रहों का अवलोकन करने की अपील की है।

## ►► न्यूज ब्रीफ

### शीत ऋतु का आगमन के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या



**भाटापारा।** जैसे-जैसे शीत ऋतु ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, वैसे-वैसे तापमान में गिरावट के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। सुबह और शाम की चुभती ठंड तथा बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, और सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा जा रहा है। तापमान में अचानक बदलाव और कम धूप मिलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है जिससे फ्लू वायरस तेजी से फैलता है। इसके चलते बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी-खांसी और तेज बुखार की शिकायत आम हो गई है। ठंडी हवा फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देती है, जिससे सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही, सर्दियों की शुरूआत में धुंध और प्रदूषण के कण हवा में नीचे बैठ जाते हैं, जो दमा और सीओपीडी के मरीजों के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं। ठंड के मौसम में जोड़ों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड सकुर्लेशन कम होता है और गठिया के मरीजों में जोड़ों का दर्द व जकड़न बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंड के दौरान शरीर का नर्वस सिस्टम सक्रिय होने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी गंभीर दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है।

### धान खरीदी से पहले राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से समस्या बढ़ी

**भाटापारा।** 15 नवंबर से राज्य शासन ने धान खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की है। और धान खरीदी से पहले ही राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल एक बड़ा संकट बन गया है। प्रदेश क पटवारी संघ अपने हड़ताल को जारी रखे हुए है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के कर्मचारियो ने आज एक दिन का आवकाश रखा है। इसके साथ ही धान खरीदी कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। खरीदी केन्द्रो में जो आवश्यक व्यवस्थाये है उसमें अव्यवस्था देखी जा रही है। इसके साथ ही किसानों के पंजीयन वास्तविक कृषि रकबे से पंजीयन में रकबा का भिन्न होना या कम होना दर्ज की गई। फसल जानकारी में अंतर पाया जाना जैसे कई गंभीर समस्याएं इसको लेकर बनी हुई है। धान के रकबे और डिजीटल सर्वे से जुड़ी समस्याए गंभीर रूप ले चुकी है साथ ही तकनीकी दिक्कतो के कारण किसानों का जीना हराम है पहले ही मौसम के मार से किसान अधमरे है। अब इसके साथ ही नई समस्या आन खड़ी हुई है। किसानो का कहना है की रकबे में वास्तविकता और पंजीयन में अंतर है जिसकी जांच कर तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए नही तो धान विक्रय में बड़ी परेशानी होगी। डिजीटल क्राप सर्वे में भी बहुत सारी गलतियां है जिसमें गलत जानकारी दर्ज की गई है जिसका सुधार किया जाना बेहद जरूरी है । शासन को इन समस्याओं को देखते हुए तत्काल ही इस पर निर्णय लेते हुए समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए।



# दीपावली मिलन समारोह एवं समरसता भोज में एक मंच पर जुटा भाजपा परिवार

### वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया संगठन का मंत्र

समवेत शिखर संवाददाता



**गरियाबंद।** दीपावली के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी जिला गरियाबंद द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह एवं समरसता भोज का भव्य आयोजन किया गया।

उत्साह, उमंग और आत्मीयता के वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन की एकजुटता और सामाजिक समरसता की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल,महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद रूपकुमारी चौधरी,छत्तीसगढ़ भंडारगृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, भाजपा जिला संगठन प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी,राजिम विधायक रोहित साहू,भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर,पिछडा वर्ग आयोग अध्यक्ष नेहरु निषाद पूर्व विधयाक संतोष उपाध्याय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भाजपा कार्यालय मे दीपावली मिलन समारोह इस बार बेहद उत्साह और अनोखे अंदाज में मनाया गया। आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर और एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देकर खुशियां साझा की गईं।समारोह में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ संगठनात्मक विषयों,सरकार की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की भूमिका,संगठन की मजबूती,सरकार की जनकल्याणकारी पहल और जनसेवा के महत्व को रेखांकित किया।

छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने कार्यकर्ताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों,महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।सरकार की योजनाओं का उद्देश्य आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने किसानों के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए बताया की खरीफ विपणन सत्र से पहले राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल धान विक्रय की अनिवार्य बाध्यता खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसान अब अपनी जरूरत और सुविधानुसार ही धान बेच सकेंगे। काश्तकारों को बेची गई मात्रा पर समर्थन मूल्य और 21 क्विंटल के दायरे में शेष बची उपज पर 'कृषक उन्नति योजना के तहत सीधे अंतर राशि (बोनस) का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं और उनकी आर्थिक समृद्धि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।

महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं को दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम, निष्ठा और सेवा भावना से ही संगठन निरंतर मजबूत होता है। उन्होंने संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने, आम जनता के बीच सक्रिय रहने और समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का मार्गदर्शन दिया।

भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि दीपावली मिलन समारोह एवं समरसता भोज जैसे आयोजन संगठन के लोगों को एक परिवार के रूप में जोड़ने का काम करते हैं।आपसी मेल-मिलाप, सहयोग और समरसता से संगठनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होते हैं।उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान उसके समर्पित कार्यकर्ताओं से है। संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उन्होंने जिले में संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।छत्तीसगढ़ भंडारगृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने भी समारोह को संबोधित करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में संगठन की विचारधारा, कार्यकर्ताओं के दायित्व और आपसी समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की एकजुटता, समर्पण और सक्रियता से सुनिश्चित होती है। सभी कार्यकर्ताओं को समाज के बीच रहकर जनहित के कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक साथ समरसता भोज में सहभागिता की। दीपावली के उल्लास के बीच आयोजित इस समारोह में राजनीतिक गतिविधियों के साथ आपसी सद्भाव, भाईचारे और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देखने को मिला। यह आयोजन भाजपा परिवार के बीच आत्मीय संबंधों को मजबूत करने और सामूहिक रूप से संगठन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर बना।इस अवसर पर रामकुमार साहू जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप चंद्रशेखर साहू सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश सहसंयोजक मुरलीधर सिन्हा जिला उपाध्यक्ष गुरुनारायण तिवारी,प्रीतम सिन्हा, ईश्वर साहू,पदुलोचन जगत,केशरी ध्रुव, सरिता ठाकुर,जिला कोषाध्यक्ष अजय रोहरा जिला मंत्री सुरेंद्र सोनटेके महिला मोर्चा अध्यक्ष बिंदु सिन्हा किसान मोर्चा अध्यक्ष हलमन धुर्वा युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक साहू अजजा मोर्चा अध्यक्ष सियाराम ध्रुव अजा मोर्चा अध्यक्ष उत्तम राजवंशी मंडल अध्यक्षगण प्रकोष्ठ के संयोजक गण सहित जिलेभर के भाजपा पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

## 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत हथनीपारा मंडल द्वारा जनचौपाल आयोजित



समवेत शिखर संवाददाता

**भाटापारा।** अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोकतंत्र की रक्षा, मतदाता सूची में पारदर्शिता एवं प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्लॉक के हथनी मंडल में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत जनचौपाल का आयोजन किया गया।

इस दौरान वार्ड वासियों से चर्चा कर मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं एवं सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। उक्त कार्यक्रम में विधायक इन्द्र साव ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के वोट की रक्षा जरूरी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता सूची की जांच में लोगों की मदद करेंगे। उक्त कार्यक्रम में सतीश अग्रवाल, सुशील शर्मा, आलोक मिश्रा, गौरी भृगु ,अरुण यदु ,अय्यूब बांठिया, दिवाकर मिश्र, पुनीत दास मानिकपुरी,राजकुमार शर्मा, नानू सोनी नितिन शुक्ला लक्ष्मी पांडे, नवीन बख्शा, विमल शर्मा आशीष वर्मा ,गुड्डा मानिकपुरी, हंसराज बंसल मनमोहन कुर्रे ,राजा तिवारी ,मोहन निषाद सीता साहू ,दुर्गेश साहू, कृष्ण कुमार साहू, खोमलाल साहू ,दानीभाट, पूर्णिमा श्रीवास, शान्ति ध्रुव, पुनाराम साहू, नारायण मानिकपुरी, सहित कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

## आरंग में जन चौपाल के जरिए कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

### डॉ. शिवकुमार डहरिया बोले-वोट चोरी से सत्ता में आई भाजपा सरकार

समवेत शिखर संवाददाता



**आरंग।** प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया के मार्गदर्शन में आरंग शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय बस स्टैंड में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' एवं 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' अभियान के तहत मंडल स्तरीय विशाल जन चौपाल-संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरंग विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों, आम जनता से जुड़े मुद्दों, महंगाई, बिजली बिलों में बढ़ोतरी तथा प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई।

**भाजपा सरकार पर डॉ. डहरिया का तीखा हमला**–कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता के वास्तविक जनादेश से नहीं, बल्कि वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चला रही है।

डॉ. डहरिया ने कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में आज जो भी प्रमुख विकास कार्य और संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, उनमें से अधिकांश कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत एवं निर्मित किए गए थे। वर्तमान भाजपा सरकार उन्हीं कार्यों का लोकार्पण और फीता काटकर अपनी उपलब्धि बताने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है और नए विकास कार्यों की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

**महंगाई और बढ़ते बिजली बिल से आम जनता परेशान**–पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों में हो रही वृद्धि से आम नागरिकों का बजट बिगड़ गया है। आम आदमी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने में सरकार विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े इन मुद्दों को लेकर पार्टी सड़क से सदन तक अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

**बाजार में दुकानदारों और राहगीरों को बांटे पोस्टर**–जन चौपाल-संवाद के पश्चात पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आरंग शहर अध्यक्ष खिलावन निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बाजार क्षेत्र में पहुंचकर दुकानदारों एवं राहगीरों को अभियान से संबंधित पोस्टर वितरित किए। इस दौरान केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए लोगों को वोट की ताकत, लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आरंग शहर अध्यक्ष खिलावन निषाद, मंडल अध्यक्ष भरत लोधी, दीपक चंद्राकर, मंगलमूर्ति अग्रवाल, शरद गुप्ता जीतू, ईश्वर पटेल, समीर गोरी, सजल चंद्राकर, उपेंद्र साहू, तुलसी पटेल, दिलीप चंद्राकर, मंजू चंद्राकर, देवेंद्र धृतलहरें, मुकेश लोधी, राकेश मिश्रा, चोवा जलक्षत्रि, भीम जलक्षत्रि, सलमा बेगम, बिजेंद्र लोधी, हेमा जलक्षत्रि, राजेश्वरी साहू, गौरीबाई देवांगन, भारती देवांगन, चम्मन कोसले, जय डहरिया, आचूं देवांगन, सादिक बेलीम, चमन जलक्षत्रि, डोमनलाल ध्रुव, मोरध्वज साहू, बलराम पाल, शेखर लोधी, सुनील बघेल, गोलू चंद्रहास साहू, राममोहन लोधी, सागर जोशी, आलोक चंद्राकर, सलमान खान, चंद्रहास साहू, राजू लोधी, कैलाश बंजारे, गणेशराम साहू, खेलावन राम, दयालुराम साहू, मनेश कंडरा एवं भोला यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक उपस्थित थे।

## चमन बने भुसरेंगा सहकारी समिति के अध्यक्ष, ग्रामीणों में हर्ष

समवेत शिखर संवाददाता



**कुरूद।** ग्राम भुसरेंगा में सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। जिसमें चमन निर्मलकर को सर्वसम्मति से भुसरेंगा सहकारी समिति का नया अध्यक्ष चुना गया।जानकारी के अनुसार सहकारी समिति की बैठक में ग्राम के सभी सदस्यों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया। चमन निर्मलकर के अध्यक्ष बनते ही ग्राम में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर चमन निर्मलकर ने कहा कि वे समिति के माध्यम से किसानों के हित में कार्य करेंगे और ग्राम के विकास कार्यों को गति देंगे। उन्होंने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम के हर्षवर्धन चंद्राकर, सरपंच प्रतिनिधि खिलेन्द्र साहू, पंच विजय कुमार साहू, ललित दीवान, मुन्ना साहू, रुपेश निर्मलकर, गप्पू साहू, मोहित साहू, जागेश्वर निर्मलकर, शेष निर्मलकर, चेतन साहू, व्यासनारायण साहू, अकलेश निर्मलकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

## खरीदी में बड़ा बदलाव, कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरे 21 क्विंटल की बोनस राशि : चंद्रशेखर साहू

समवेत शिखर संवाददाता



**फिंगेश्वर।** भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी और प्रबंधन व्यवस्था में उठाए गए कड़े कदमों को किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताया है।

सरकार के इस निर्णय से बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वालों पर बड़ा प्रहार हुआ है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और राज्य के खजाने के लगभग 12,000 करोड़ रुपये की भारी बचत होगी। क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता चंद्रशेखर साहू ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में धान खरीदी के नाम पर बिचौलियों और सटोरियों का बोलबाला था, जिससे वास्तविक किसानों का हक मारा जाता था और सरकारी खजाने को भारी चपत लगती थी। वर्तमान सरकार ने डिजिटल व्यवस्था, सख्त निगरानी और पारदर्शी नीतियों के जरिए इस खेल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है चूंकि कुछ इलाकों को छोड़ दें तो अनेक क्षेत्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार नहीं होती ऐसे में 21 क्विंटल धान बेचने के लिए बिचौलिए सक्रिय हो जाते थे और सरकारी खजाने पर भार पड़ता था अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसान हित में निर्णय लिया है कि किसान यदि 15-17 क्विंटल प्रति एकड़ भी धान बेचेंगे तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल धान की बोनस राशि दी जाएगी। इससे किसानों को कम पैदावार होने पर भी पूरी बोनस राशि की व्यवस्था सरकार ने की है जो कि किसानों के हित में आमूलचूल परिवर्तन है। भाजपा जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू ने इस दूरदर्शी और किसान-हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का आभार व्यक्त किया है। यह कदम राज्य के अन्नदाताओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दलहन तिलहन सहित अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार ने प्रोत्साहित करते हुए 15 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है इससे फसल परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही किसान अब मौसम आधारित खेती की ओर अग्रसर होंगे जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहेगी।

## गरियाबंद में कंप्यूटर ऑपरेटरों का उग्र प्रदर्शन, गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, तिरंगा चौक पर किया चक्काजाम

### 8 महीने से वेतन नहीं, ऊपर से 60 से 180 किलोमीटर दूर ड्यूटी का फरमान; आदेश वापस लेने की मांग पर सड़क पर उतरे ऑपरेटर, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

समवेत शिखर संवाददाता



**गरियाबंद।** समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले गरियाबंद जिले में कंप्यूटर ऑपरेटरों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया।महीनों से वेतन नहीं मिलने और मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर धान उपार्जन केंद्रों में संलग्नीकरण किए जाने के विरोध में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले जिलेभर के ऑपरेटरों ने अपने बच्चों सहित पूरे परिवार को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।अपनी मांगों को लेकर पहले ही प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके कर्मचारियों ने आदेश वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया।

शुक्रवार को जिलेभर के कंप्यूटर ऑपरेटर गांधी मैदान में एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तिरंगा चौक पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्काजाम किया।इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफजमकर नारेबाजी करते हुए संलग्नीकरण आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की। इसके बाद ऑपरेटरों ने बस स्टैंड से पैदल मार्च शुरू किया और गौरव पथ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की।

**8 महीने से वेतन नहीं, ऊपर से 180 किलोमीटर दूर ड्यूटी!**–कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि कई कर्मचारियों को पिछले 5 से 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में पहले से आर्थिक संकट झेल रहे ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे धान उपार्जन केंद्रों में संलग्न कर दिया गया है। अल्प मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना और रहने-खाने की व्यवस्था करना बेहद मुश्किल है। उनका सवाल है कि जब महीनों से वेतन नहीं मिला तो अतिरिक्त यात्रा और रहने का खर्च आखिर कहां से उठाएं?

**महिला ऑपरेटरों और नए केंद्रों में नियुक्त कर्मचारियों को भी परेशानी**–संघ ने आरोप लगाया कि संलग्नीकरण आदेश में महिला कर्मचारियों की पारिवारिक परिस्थितियों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। कई महिला ऑपरेटरों के छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसके बावजूद उन्हें दूरस्थ केंद्रों में भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जिले में शुरू हुए 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में पहली बार नियुक्त ऑपरेटरों को भी दूसरे ब्लॉकों में संलग्न कर दिया गया है। संघ का कहना है कि इस तरह के आदेश से कर्मचारियों के साथ-साथ उनकी मूल सहकारी समितियों का कामकाज भी प्रभावित होगा।

**कल सौंपा था ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आज सड़क पर उतर**–गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एक दिन पहले ही कलेक्टर गरियाबंद को ज्ञापन सौंपकर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी आदेश क्रमांक 688, दिनांक 7 नवंबर 2026 पर तत्काल रोक लगाने और मानवीय आधार पर संशोधन करने की मांग की थी। लेकिन मांगों पर समाधान नहीं निकलने और आदेश वापस नहीं लिए जाने से नाराज कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन और चक्काजाम किया।

**19 वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे, अब अपने ही हक के लिए संघर्ष**–संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा कि हम पिछले 19 वर्षों से सहकारी समितियों और धान उपार्जन केंद्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ किसानों की सेवा कर रहे हैं। किसानों की धान खरीदी से लेकर उनकी समस्याओं के निराकरण तक हर काम पूरी निष्ठा से करते आए हैं, लेकिन इस बार जिला सहकारिता विभाग द्वारा जारी संलग्नीकरण आदेश ने ऑपरेटरों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। गरियाबंद जिले में कर्मचारियों को उनके मूल कार्यस्थल से 60 से 170 किलोमीटर तक दूर भेज दिया गया है। राजिम के ऑपरेटरों को गोहरापदर बाजार, देवभोग क्षेत्र के कर्मचारियों को गरियाबंद और गरियाबंद के कर्मचारियों को दूसरे ब्लॉकों में भेजा गया है। यहां तक कि 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में पहली बार नियुक्त ऑपरेटरों को भी दूसरे ब्लॉकों में संलग्न कर दिया गया है। महिला ऑपरेटरों को भी नहीं बख्शा गया, जबकि कई के छोटे-छोटे बच्चे हैं।उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई ऑपरेटरों को 5 से 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में जब घर चलाने के लिए वेतन नहीं है तो 100 से 170 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करने का अतिरिक्त खर्च कहां से उठाएंगे? आने-जाने और रहने का खर्च उठाने के बाद कर्मचारियों के पास क्या बचेगा? हमने कई बार अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हमें कहा जा रहा है कि आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा ड्यूटी पर जाना पड़ेगा।

## किसानों की धान खरीदी में आ रही विसंगतियों का शीघ्र निराकरण करने की मांग

समवेत शिखर संवाददाता

**फरहदा।** क्षेत्र के अनेक किसान भाइयों के धान उपार्जन एवं विक्रय से संबंधित पंजीयन और रकबा सत्यापन में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां सामने आ रही हैं। इनमें रकबा संशोधन, नवीन पंजीयन, पुराने पंजीयन, अधिया-रेगहा पंजीयन, एग्रीस्टैक में पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा धान बोने के रकबे का दर्ज एवं सत्यापन जैसी समस्याएं प्रमुख हैं।

इन विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में किसान भाई परेशान हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो किसानों को अपनी मेहनत से उत्पादित धान फसल को शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचने एवं धान खरीदी प्रक्रिया में शामिल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

इस संबंध में समिति फरहदा के अध्यक्ष द्वारा समिति के समस्त कर्मचारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विनम्र आग्रह किया गया है कि वे किसानों की इन समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आपसी समन्वय के साथ शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

साथ ही जिन किसानों के पंजीयन, रकबा संशोधन, डिजिटल क्रॉप सर्वे अथवा सत्यापन में त्रुटियां या विसंगतियां हैं, उनका समय-सीमा के भीतर सुधार कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान खरीदी के लाभ से वंचित न रहे।

किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा निर्धारित धान खरीदी की समयावधि में सभी पात्र किसानों की धान उपज का सुचारू रूप से उपार्जन हो सके।

## न्यूज ब्रीफ

### न्यूवोको रेलवे फाटक के पास जानलेवा गड्ढा

**भाटापारा/निपनिया।** न्यूवोको रेल्वे साईडिंग के नागपुर एंड फाटक के रोड की हालत खतरनाक हो गया है। आए दिन वाहन



चालक गिर कर घायल हो रहे हैंइस व्यस्त रोड पर लगातार आना जाना लगा रहता है। उस रेल्वे फाटक पर ड्यूटी करने वाले सभी गेटकीपरो को मालूम है वे अपने उपर अधिकारियों को रोड की स्थिति के बारे में बता चुके हैं सोनाडीह के अधिकारियों को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। इसलिए रोड रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है। रोड का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है थोड़ा सी लापरवाही से बस, आटो, मोटर साइकिल दुर्घटना का शिकार हो सकता है इसी तरह न्यूवोको रेल्वे का एप्रोच रोड है जनता के उपयोग हेतु जो 35 साल पहले डब्लुबीएम रोड बनाया गया था आज उस खतरनाक रोड से कोई भी आना पसंद नहीं करता है। एप्रोच रोड हेतु कंपनी के अधिकरियों को कई बार बोला गया परंतु उनके कानों पर जू नहीं रेंगता है। आम जनता ने इस दोनों रोड को यथाशीघ्र ठीक करने का संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग एवं न्यूवोको कंपनी के संबंधित अधिकारियों से मांग किया गया है।

### भोपाल में नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू

**भोपाल।** लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इसके साथ ही भोपाल में पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोजपुरी एकता मंच समिति ने श्रद्धालुओं को ठेकुआ महाप्रसाद बनाने के लिए निःशुल्क गेहूं पिसाई की सुविधा दी है। शुक्रवार को कमला पार्क स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में आटा चक्की की पूजा-अर्चना के बाद एडीजी एससीआरबी जयदीप प्रसाद (आईपीएस) ने इसकी शुरुआत की। यह सुविधा 14 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। पर्व के पहले दिन व्रतियों ने घरों की साफ सफाई और स्नान के बाद सात्विक भोजन तैयार किया। परंपरा के अनुसार इसमें लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाकर पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है।

# धान बेचने की मात्रा के बजाय खेती के रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि देने का निर्णय : मंत्री नेताम

- प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी दी जाएगी 13839 रुपए आदान सहायता राशि
- कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये का भुगतान, फसल विविधीकरण और श्री अन्न उत्पादन को मिल रहा प्रोत्साहन
- कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं कृषि विभाग की उपलब्धियां



समवेत शिखर न्यूज

**रायपुर।** कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को नवा रायपुर संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विभागीय उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान बेचने की मात्रा के बजाय खेती के रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 13839 रुपए दिए जाएंगे। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी उसे आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी व कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि पहले योजना में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने पर समर्थन मूल्य और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर की राशि दी जाती थी। अब नई व्यवस्था में किसान 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार पूरी आदान सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी।

श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

#### आदान सहायता से किसानों को मिलेगी सुविधा

कृषि मंत्री श्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। श्री नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों द्वारा 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया जा चुका है। यह पहल धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने में सहायक होगी।

#### दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने का अवसर

कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

#### श्री अन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा

कृषि मंत्री श्री नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफविपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इनका उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी का उपार्जन भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो एवं कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी, इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री नेताम ने बताया कि राज्य सरकार की इन पहलों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उनकी उपज का उचित मूल्य और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

# किसानों के हित में बड़ा फैसला, भाजपा किसान मोर्चा ने जताया आभार

### 21 क्विंटल धान खरीदी के अंतर की राशि देने की घोषणा पर किसानों में हर्ष

समवेत शिखर संवाददाता



**आरंग।** भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी एवं महासमुंद जिला सह प्रभारी गोविंद साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के हित में की गई महत्वपूर्ण घोषणा का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

गोविंद साहू ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनने के तत्काल बाद इस घोषणा पर अमल करते हुए मंत्रालय में आदेश जारी किया गया और लगातार तीन वर्षों से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन किसानों को भी राहत देने की घोषणा की है, जिनकी प्रति एकड़ धान की पैदावार 10 से 15 क्विंटल के बीच होती है। ऐसे किसानों को भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के निर्धारित मानक के अनुरूप अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। इसके तहत 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि तथा 21 क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये का लाभ किसानों को मिलेगा।

गोविंद साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल है। किसानों के हित में लिया गया यह निर्णय सरकार की किसान हितैषी सोच और अन्नदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान इस निर्णय का स्वागत करते हुए मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

उन्होंने प्रदेश के समस्त किसान भाइयों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार आगे भी किसानों की खुशहाली, समृद्धि और आर्थिक मजबूती के लिए इसी तरह महत्वपूर्ण कदम उठाती रहेगी। गोविंद साहू ने पुनः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा– जय जोहार, जय श्रीराम। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता के के भारद्वाज, सूरज शर्मा गणेश साहू दिलीप जलक्षत्रि, विक्की साहू, खूबचंद साहू सुशील जलक्षत्रि, अशोक चंद्राकर, तोषण साहू उपस्थित रहे।

# वार्ड 6 व 7 में सीसी रोड निर्माण पर पार्षद ने उठाए सवाल, 10 लाख रुपए के खर्च पर जताई आपत्ति

### नगर पंचायत उपाध्यक्ष और पार्षदों ने सीसी सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

समवेत शिखर संवाददाता



**अंबिकापुर-लखनपुर।** सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में सीसी रोड निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। नगर पंचायत परिषद की बैठक के बाद वार्ड क्रमांक 06 एवं 07 में कराए गए सीसी रोड निर्माण को लेकर पार्षद पूनम राकेश साहू ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को लिखित आवेदन सौंपकर निर्माण कार्य की शिकायत दर्ज कराई है।

पार्षद पूनम राकेश साहू ने अपने शिकायत आवेदन में आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 06 एवं 07 में कराया गया सीसी रोड निर्माण नियमों के विपरीत है। उनके अनुसार जिस स्थान पर सड़क का निर्माण कराया गया है, वहां इसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है और न ही इस मार्ग से आम लोगों का आवागमन होता है। पार्षद का कहना है कि न तो स्थानीय लोगों द्वारा इस सड़क की मांग की गई थी और न ही इसकी कोई आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके बावजूद लगभग 10 लाख रुपये की शासकीय राशि खर्च कर सड़क का निर्माण कराया गया, जो सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला हो सकता है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सड़क निर्माण के दौरान राजस्व एवं वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। निर्माण कार्य के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति नहीं लिए जाने तथा वैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी किए जाने की बात भी आवेदन में कही गई है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि आमजन की जरूरतों को दरकिनार कर कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण कराया गया है।

पार्षद ने नगर पंचायत प्रशासन से निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नगर पंचायत स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह इस मामले को लेकर कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत करेंगी।

नगर पंचायत परिषद बैठक के बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष नेहा सनी बंसल पार्षद पूनम साहू, शमीम खान, लक्ष्मी सिंह राठौर एल्डरमैन प्रदीप गुप्ता सहित अन्य सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जहां उन्होंने सड़क निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जताई है पार्षद पूनम साहू ने आरोप लगाया है व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य या सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है।

#### शिकायत मिली है, आवेदन देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा : सीएमओ

मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि सीसी रोड निर्माण को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत पत्र का अवलोकन करने के बाद ही इस संबंध में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा।

फिलहाल पार्षद की शिकायत के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में सीसी रोड निर्माण की उपयोगिता, स्वीकृति प्रक्रिया और कथित भूमि अतिक्रमण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि नगर पंचायत प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और जांच में निर्माण कार्य को लेकर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या सामने आती है।

# कम उत्पादन के बावजूद पूरा बोनस देने के फैसले से कोई भी पात्र किसान जनकल्याणकारी सहायता से वंचित नहीं रहेगा : अलका चंद्राकर

### 'कृषक उन्नति योजना' की शर्तों में ऐतिहासिक राहत पर अलका चन्द्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार, प्रदेश के किसानों को दी बधाई

समवेत शिखर संवाददाता



**बागबाहरा।** छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी 'कृषक उन्नति योजना' के नियमों में बदलाव करते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय की बाध्यता को समाप्त करने के निर्णय का इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) की स्वतंत्र निदेशक एवं भारतीय जनता पार्टी की पंचायत प्रकोष्ठ की प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अलका चन्द्राकर ने स्वागत किया है। श्रीमती चन्द्राकर ने इस संवेदनशील और किसान हितैषी फैसले के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्त किसान भाई-बहनों को बधाई दी है।

इस्पात मंत्रालय की स्वतंत्र निदेशक और पंचायत प्रकोष्ठ की प्रदेश सह कोषाध्यक्ष श्रीमती चन्द्राकर ने कहा कि पूर्व में 'कृषक उन्नति योजना' के तहत प्रति एकड़ ?13,839 की पूरी आदान सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य था। मौसम की अनिश्चितता, भूमि की उर्वरता में अंतर या अन्य प्राकृतिक कारणों से जिन किसानों का उत्पादन कम होता था, वे पूरी सहायता राशि से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों की इस व्यावहारिक पीड़ा को समझा और इस अनिवार्य शर्त में राहत देने का बड़ा ऐलान किया है। अब यदि किसी किसान का उत्पादन कम हुआ है और वह प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान भी बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ पूरी ?13,839 की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ?श्रीमती चन्द्राकर ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ प्रदेश के छोटे, सीमांत और जनजातीय (आदिवासी) अंचल के किसानों को मिलेगा, जिनकी जोत का आकार छोटा है और जहाँ सिंचाई के साधन सीमित हैं। यह फैसला सुनिश्चित करेगा कि कम उत्पादन के बावजूद कोई भी पात्र किसान शासन की जनकल्याणकारी सहायता से वंचित न रहे। श्रीमती चन्द्राकर ने इसे 'मोदी की गारंटी' और राज्य सरकार की 'अंत्योदय' की भावना को साकार करने वाला एक मील का पत्थर बताया है।

# बाल दिवस पर विशेष : जब बच्चों ने संस्कृत को दी तकनीक की नई आवाज

### अंबिकापुर सैनिक स्कूल में बिना अतिरिक्त खर्च बनी संस्कृत लैब, कैडेट्स ने कबाड़ से बनाए सीखने के अनोखे यंत्र; देश के 33 सैनिक स्कूलों में यह अपनी तरह की अनूठी पहल

अमृता तिवारी

**रायपुर।** संस्कृत को अक्सर कठिन व्याकरण, श्लोकों और पुरानी किताबों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अंबिकापुर सैनिक स्कूल के कैडेट्स ने संस्कृत को देखने और सीखने का एक बिल्कुल अलग रास्ता खोज निकाला है। यहां संस्कृत अब सिर्फकिताबों में नहीं, बल्कि कंप्यूटर, मोबाइल एप, कियोस्क मशीन, रोचक प्रयोगों और बच्चों द्वारा बनाए गए यंत्रों के जरिए सीखी जा रही है।

देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में अंबिकापुर सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है, जहां संस्कृत की विशेष लैब तैयार की गई है। खास बात यह है कि इस लैब को तैयार करने के लिए स्कूल पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला गया। स्कूल के मेधावी बच्चों ने उपलब्ध और अनुपयोगी सामान से अलग-अलग शिक्षण यंत्र तैयार कर इस लैब को आकार दिया है।

इस संबंध में संस्कृत शिक्षक सौरभ कुमार जैन बताते हैं कि इस प्रयोग की शुरुआत एक साधारण-सी बात से हुई। उन्होंने देखा कि बच्चे संस्कृत पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, जितनी रुचि उन्हें कंप्यूटर और तकनीक में थी। यहीं से उन्होंने दोनों को जोड़ने का विचार किया। 'जब बच्चों का रुझान तकनीक की तरफहै तो संस्कृत को भी तकनीक से क्यों न जोड़ा जाए?' इसी सोच ने आगे चलकर संस्कृत सीखने के कई नए प्रयोगों को जन्म दिया।

#### सांप-सीढ़ी से सीख रहे संधि

लैब का एक और खास आकर्षण है 'संधि सांप-सीढ़ी' यंत्र। खेल के रूप में तैयार किए गए इस यंत्र के जरिए बच्चे संधि के नियमों को समझते और उनका अभ्यास करते हैं। पढ़ाई और खेल का यह मेल बच्चों के लिए सीखने को आसान और रोचक बना रहा है।



#### मोबाइल एप ने संस्कृत को पहुंचाया स्कूल की दीवारों से बाहर

संस्कृत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की इसी सोच से संस्कृत लर्निंग ऐप भी तैयार किया गया। शिक्षक सौरभ कुमार जैन के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने इसमें संस्कृत सीखने और अभ्यास से जुड़ी सामग्री को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इसका लाभ अब केवल सैनिक स्कूल के बच्चे ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी उठा रहे हैं।

#### बेकार पड़े प्रिंटर के रोलर से बना 'चक्रवाह यंत्र'

लैब में मौजूद 'चक्रवाह यंत्र' भी बच्चों की रचनात्मकता का उदाहरण है। इसे पुराने और अनुपयोगी पड़े प्रिंटर के इंक रोलर से तैयार किया गया है। यंत्र को घुमाने पर बच्चों को संस्कृत से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां मिलती हैं। यानी जो सामान कभी बेकार समझकर अलग कर दिया जाता, बच्चों की कल्पना ने उसे भी शिक्षण सामग्री में बदल दिया।

#### सही संख्या चुनते ही जल उठती है लाइट

'संख्या यंत्र' बच्चों को संस्कृत में संख्याएं सीखने का मौका देता है। इसमें संस्कृत और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में संख्याएं दी गई हैं। बच्चे जब संस्कृत संख्या का सही अंग्रेजी संख्या से मिलान करते हैं तो लाइट जल उठती है। लाइट का जलना उनके सही उत्तर का संकेत होता है। इस तरह बच्चे बिना किसी दबाव के खेल-खेल में संस्कृत की संख्याएं सीख लेते हैं।

#### संस्कृत में भी पढ़ी जा सकती है स्कूल की वेबसाइट

अंबिकापुर सैनिक स्कूल की पहल केवल लैब तक सीमित नहीं है। देश के 33 सैनिक स्कूलों में अंबिकापुर सैनिक स्कूल की वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी पढ़ा जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि वेबसाइट को संस्कृत रूप देने के काम में भी बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

#### कियोस्क मशीन से आसान हुई संस्कृत

लैब में लगी कियोस्क मशीन बच्चों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके माध्यम से बच्चे संस्कृत भाषा से जुड़ी सामग्री को तकनीक के जरिए आसानी से समझ और सीख रहे हैं। यानी जिस तकनीक को बच्चे आमतौर पर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही अब उनके लिए भाषा सीखने का माध्यम बन गई है।

#### बच्चे सिर्फ सीख नहीं रहे, बना भी रहे हैं

इस पूरी पहल की सबसे खास बात यही है कि यहां बच्चे तकनीक के केवल इस्तेमालकर्ता नहीं हैं, बल्कि निर्माता भी हैं। उन्होंने अपनी कल्पनाशक्ति, उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी समझ का इस्तेमाल ऐसे उपकरण बनाने में किया, जो दूसरे बच्चों को संस्कृत सीखने में मदद कर रहे हैं।

बाल दिवस पर अंबिकापुर सैनिक स्कूल की यह कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह केवल संस्कृत पढ़ाने की कहानी नहीं है। यह उस सोच की कहानी है, जिसमें परंपरा और तकनीक एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथी बन सकते हैं।

संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा जब बच्चों की कल्पना और आधुनिक तकनीक से जुड़ती है तो वह उन्हें बोझिल विषय नहीं, बल्कि प्रयोग और खोज का अवसर लगने लगती है।शायद यही बाल दिवस का सबसे सुंदर संदेश भी है–बच्चों को केवल कुछ सिखाया न जाए, बल्कि उन्हें कुछ नया बनाने का अवसर भी दिया जाए। क्योंकि सही मार्गदर्शन और थोड़ी-सी आजादी मिले तो बच्चे न केवल भविष्य के लिए तैयार होते हैं, बल्कि आज ही भविष्य की नई राह बना सकते हैं।

### भाटापारा में 16 को राउत नाच महोत्सव का आयोजन



**भाटापारा।** छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति की अमूल्य धरोहर राऊत नाचा 16 नवम्बर को रामलीला मैदान में आयोजित किया गया है। जिसमें अंचल के 20 से ज्यादा नर्तक दल शामिल होकर नृत्यकला के साथ शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन समिति के प्रमुख रमेश यदु पूर्व मंडी उपाध्यक्ष ने बताया कि इस आयोजन मे अंचलों से 20 से ज्यादा दल शामिल होकर अपनी बहुरंगी नृत्य कला एवं शस्त्र चालन कला का प्रदर्शन करेंगे। जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसके अलावा महोत्सव में अलग-अलग प्रदर्शन, गायन, अनुशासन के आधार पर भी दल के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी पुरस्कृत किया जाएगा। महोत्सव को सफल बनाने नरेंद्र यदु, चंद्रकांत यदु,धनीराम यदु,संतोष यदु, शिव यदु,ओमप्रकाश यदु, रवि यदु, सुरेश यादव, मुरली मनोहर यादव,राजु यादव तिल्दाबंधा, सुरेश यदु,दुर्गेश यदु, रोशन यदु, अरविन्द यदु ,सतीश यादव, योगेश यदु,कमल नारायण यदु, कैलास यदु, बबला यादव, सुशील यादव, धन्नू यादव, अजय यदु आदि जुटे हुए है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक देवीचंद श्रीश्रीमाल द्वारा समवेत शिखर प्रेस, रजबंधा मैदान, रायपुर से मुद्रित कर प्रकाशित। संपादक : देवीचंद श्रीश्रीमाल, प्रबंध संपादक : विवेक श्रीश्रीमाल, समाचार संपादक: शंकर चंद्राकर*

( * पीआरबी एक्ट के तहत संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार) आर.एन.आई. रजि. क्र.- 52151/91, पो. रजि. नं.-सीजी/आरवाईपी डी.एन./ 28/2026-28 फोन : 0771-4334967, Email : news@samvetshikhar.com, www.samvetshikhar.com

## ►► न्यूज ब्रीफ

### आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

**कांकेर।** कलेक्टर कुन्दन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में मृतक के आश्रित के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। चारामा निवासी 62 वर्षीय प्रीतराम मरकाम की मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती अंकलहिन के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार चारामा द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

### कार्यशाला में दिया गया वन धन विकास केंद्र के संचालन का प्रशिक्षण

**जगदलपुर।** बस्तर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले के बकावंड, तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा विकासखंड में तीन नए वनधन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ट्राईफेड इंडिया के संयुक्त समन्वय से स्थापित होने वाले इन केंद्रों का संपूर्ण संचालन स्वयं सहायता समूह की बिहान दीदियां करेंगी। इन केंद्रों के सुचारू संचालन और प्रत्येक केंद्र के लिए स्वीकृत 15 लाख रुपये के बजट के प्रभावी व्यय पर समझ विकसित करने के उद्देश्य से आज जिला पंचायत बस्तर के विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) शाखा में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वनधन केंद्रों के तहत गठित समितियों के पदाधिकारियों सहित ब्लॉक स्तर के बीपीएम, क्षेत्रीय समन्वयक (एसी), एफपीसी सीईओ और उत्पादक समूह (पीजी) के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान ट्राईफेड इंडिया से आए प्रतिनिधि श्री अमित दुबे, वन विभाग से श्री अविनाश जी कीर्तिवर्धन, बिहान के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयकों ने प्रतिभागियों को केंद्र के दैनिक संचालन, सदस्यों की भूमिका तथा वनोपजों के वैज्ञानिक संग्रहण, सुरक्षित भंडारण और प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। इसके साथ ही स्वीकृत 15 लाख रुपये के बजट का किन-किन मदों में उपयोग किया जाना है, बिल-वाउचर का सही संधारण कैसे हो और लेखा-जोखा में पूर्ण पारदर्शिता कैसे रखी जाए, इस पर भी गहन चर्चा की गई। कार्यशाला में बकावंड, तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा केंद्रों के लिए आगामी कार्ययोजना तैयार करते हुए क्षेत्र की प्रमुख वनोपजों जैसे महुआ, इमली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद और लाख को प्रसंस्करण हेतु चिन्हांकित किया गया। विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दीदियां कच्चा वनोपज बेचने के बजाय उनका प्रसंस्करण कर आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग करें, ताकि ट्राईफेड के माध्यम से उन्हें बड़े बाजारों से जोड़कर अधिक मुनाफा कमाया जा सके। कार्यशाला में ट्राईफेड के प्रतिनिधि श्री अमित दुबे ने कहा कि वनधन केंद्र केवल वनोपज संग्रहण का स्थान नहीं हैं, बल्कि यह दीदियों का अपना उद्यम है।

# माओवाद की हिंसा से क्षतिग्रस्त आश्रम-छात्रावासों का फिर होगा पुनर्निर्माण, बुरगुम, पोटाली, नहाड़ी और समेली में हुआ भूमिपूजन

समवेत शिखर संवाददाता

**दंतेवाड़ा।** जिले के दूरस्थ एवं अंतिम छोर के गांवों में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। माओवाद की हिंसा के चलते वर्ष 2007-08 में ध्वस्त किए गए आश्रम-छात्रावासों का अब पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में बुरगुम, पोटाली, नहाड़ी और समेली में आश्रम-छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के करकमलों से किया गया। प्रत्येक आश्रम-छात्रावास 50 सीटर क्षमता का होगा। इन चारों छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रति आश्रम 162.76 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। इस प्रकार चारों आश्रम-छात्रावासों के निर्माण पर कुल 651.04 लाख रुपये अर्थात लगभग 6 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।



वर्ष 2007-08 में माओवादी हिंसा के कारण इन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों एवं आश्रम-छात्रावासों को भारी नुकसान पहुंचा था। लंबे समय से इन दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आवासीय शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब इन छात्रावासों के पुनर्निर्माण से स्थानीय बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि आज बुरगुम, पोटाली, नहाड़ी और समेली ग्राम पंचायतों में आश्रम-छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु भूमिपूजन होना क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2007-08 में माओवादी हिंसा के कारण इन छात्रावासों को ध्वस्त कर दिया गया था। लंबे समय से इन क्षेत्रों के बच्चे बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाओं की अपेक्षा कर रहे थे। अब छात्रावासों के पुनर्निर्माण से उन्हें सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हमारा संकल्प है कि इन दूरस्थ अंचलों के बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर अपने क्षेत्र, समाज और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों तक आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। यहां लौह अयस्क के साथ चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ और कोटमसर जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरें मौजूद हैं। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पुल-पुलिया, सीसी रोड, आंगनबाड़ी भवन एवं माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण भी प्राथमिकता से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इन क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर गांवों की तस्वीर बदलना हमारा लक्ष्य है। आने वाले समय में इन विकास कार्यों को गति देकर ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री चैतराम अटामी ने कहा कि बुरगुम, पोटाली, नहाड़ी और समेली में आश्रम-छात्रावासों के पुनर्निर्माण से दूरस्थ अंचलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।

# ट्रेड लाइसेंस के नाम पर टैक्स वसूली का आरोप, पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने सरकार को घेरा

समवेत शिखर संवाददाता

**जगदलपुर।** नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर नई वसूली की तैयारी को लेकर शहर की राजनीति गरमा गई है। पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने राज्य सरकार पर बजट में नया टैक्स नहीं लगाने का दावा करने के बाद राजपत्र के माध्यम से पिछले दरवाजे से कर वसूली का आरोप लगाया है।



जायसवाल ने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रावधानों के तहत अब ठेले-खोमचे से लेकर बड़े शोरूम, होटल और ट्रैवल एजेंसी तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाया जा रहा है।

**क्या है पूरा मामला :** पूर्व महापौर के अनुसार, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना, कारखाना अधिनियम, व्यावसायिक सुरक्षा तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन के नाम पर ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा।

इसके तहत प्रस्तावित दर इस प्रकार है - कॉलोनी क्षेत्र - 4 रुपये प्रति वर्गफुट, छोटे बाजार -5 रुपये प्रति वर्गफुट, बड़े बाजार- 6 रुपये प्रति वर्गफुट, अधिकतम सालाना सीमा -30 हजार रुपये, हर 2 साल में - 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव

**कौन-कौन आएगा दायरे में :** प्रस्तावित व्यवस्था में ठेले-खोमचे, ऑटो रिक्शा, गुमटी, किराना दुकान, डेयरी, पैकेज्ड फूड कारोबार, होटल, लॉज, सिनेमा हॉल और ट्रैवल एजेंसी तक को शामिल किया गया है। जायसवाल का कहना है कि इससे छोटे कारोबारी सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जो पहले से ही महंगाई और टैक्स के बोझ से जूझ रहे हैं।

# धान पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से मिलेगी 13839 रुपए की कृषि आदान सहायता राशि

समवेत शिखर संवाददाता

**दंतेवाड़ा।** छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब किसानों को प्रति एकड़ पूरे 21 क्विंटल धान के मान से कृषि आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा, भले ही किसी किसान के खेत में एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान पैदा हुआ हो। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 से लागू इस व्यवस्था को किसान हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को मिलेगा जो रासायनिक खाद छोड़कर जैविक और प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। जिला दंतेवाड़ा में ऐसे पंजीकृत जैविक किसानों की संख्या 10,264 है।

किसानों के लिए यह फैसला ऐसे समय आया है जब दंतेवाड़ा जिले के कृषि कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दंतेवाड़ा जिले को ÒCertificate of E&cellence से सम्मानित किया है। दंतेवाड़ा के साथ मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ और सीधी जिलों को भी यह सम्मान मिला है।

कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में जिले में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार काम हो रहा है। जनजातीय बहुल जिले के लिए यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। यह कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी, मछलीपालन विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, मैदानी अमले और किसानों के सामूहिक प्रयासों की जीत है। अब कृषि आदान सहायता राशि के नए फैसले से जिले के जैविक किसानों का उत्साह और बढ़ेगा।

**जैविक किसानों की सबसे बड़ी चिंता खत्म :** जैविक खेती शुरू करने वाले किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि शुरुआती वर्षों में पैदावार कुछ कम हो सकती है। अब तक कृषि आदान सहायता वास्तविक उत्पादन से जुड़ी होने के कारण कम पैदावार का सीधा असर किसान की आय पर पड़ता था। नए फैसले के बाद कृषि आदान सहायता राशि प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल के आधार पर मिलेगी। यानी जैविक किसान को अब कम उत्पादन के कारण आर्थिक नुकसान की चिंता नहीं रहेगी। यह निर्णय रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा देने की दिशा में देशभर के लिए एक मॉडल बन सकता है।

# एनआईएफटी में चयनित एकलव्य विद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

समवेत शिखर संवाददाता

**सुकमा।** जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, निरंतर प्रोत्साहन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता का सुखद परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा के चार होनहार विद्यार्थियों आशा रवा, ममता, अनिता बघेल और लक्ष्मण बारसे ने देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर पूरे सुकमा जिले का मान बढ़ाया है। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के तहत 12 नवंबर 2026 को आयोजित इस गरिमामय समारोह में इन विद्यार्थियों ने देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सीधे संवाद कर सुदूर अंचल की प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम एवं NESTS की आयुक्त डॉ. प्रतिमा से भी भेंट कर भविष्य के लक्ष्यों हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। विद्यार्थियों की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे जिला प्रशासन का कुशल नेतृत्व और अटूट सहयोग एक मजबूत आधार स्तंभ बनकर उभरा है। सुकमा कलेक्टर श्री अमित कुमार के विशेष प्रोत्साहन एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा सहायक आयुक्त श्री हेमंत कुमार सिन्हा के सक्रिय सहयोग से जिले के जनजातीय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल अवसर प्राप्त हुए। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और निरंतर मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्र के इन चारों विद्यार्थियों ने देश के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 2026 की प्रवेश परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। इसमें आशा रवा, ममता और अनिता बघेल ने ह्वह्वस्रञ्ज रायपुर तथा लक्ष्मण बारसे ने ह्वह्वस्रञ्ज भोपाल में प्रवेश प्राप्त कर जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रशासन की नीतियों को धरातल पर उतारने में विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की समर्पित टीम ने भी सराहनीय भूमिका निभाई है।

## खेल-व्यापार-मनोरंजन

# कुमामोतो मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत हुए बाहर

**नई दिल्ली (ए)।** भारत के अनुभवी खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया लेकिन किदांबी श्रीकांत एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और सीधे गेम में हारकर से बाहर हो गए। विश्व के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने 40 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल मैच में जापान के युशी तनाका को 21-16, 21-15 से पराजित किया। इस भारतीय खिलाड़ी के लिए यह जीत बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें चीन में होने वाले सत्र के आखिरी टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने के लिए बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर रैंकिंग के शीर्ष आठ में जगह बनानी होगी।



हाल में हाइलो ओपन जीतने वाले आठवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य वर्तमान में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर रैंकिंग में 64,980 अंकों के साथ 12वें स्थान पर हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई खिलाड़ी अल्वी फरहान से होगा। भारतीय खिलाड़ी ने विश्व में 10वें नंबर के फरहान के खिलाफ अभी तक दो मैच खेले हैं जिनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले विश्व के 31वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत एक बार फिर अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने में नाकाम रहे। पहले गेम में उन्होंने अपने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा लेकिन दूसरे गेम में वह अच्छी बढ़त का फायदा नहीं उठा पाए और जापान के विश्व के 15वें नंबर के खिलाड़ी कोकी वातानाबे से 22-24, 15-21 से हार गए। भारतीय खिलाड़ी ने बृहस्पतिवार को जापान के विश्व के आठवें नंबर के खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप में दो बार के रजत पदक विजेता कोडाई नाराओका को हराया था लेकिन वातानाबे के खिलाफ वह अपनी इस लय को बरकरार नहीं रख पाए। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता श्रीकांत ने पहला गेम करीबी अंतर से गंवाने के बाद दूसरे गेम में 12-5 की बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई गलतियां की जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा।

# न्यूजीलैंड के खिलाफ 244 रन से हारा भारत, श्रेयस अय्यर ने पिच में बदलाव को ठहराया जिम्मेदार

**नई दिल्ली।** भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने शुक्रवार को चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों मिली 244 रन की करारी हार का ठीकरा पिच की प्रकृति मे बदलाव पर फोड़ते हुए कहा कि पहले यह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी लेकिन बाद में इससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलने लग गई थी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए लेकिन भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 26.4 ओवर में 89 रन पर आउट हो गई।

तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 27 रन देकर छह विकेट लिए। वनडे में पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है लेकिन दोनों पारियों की विकेट में बहुत बड़ा अंतर था।'' अय्यर ने कहा, ''लेकिन हेनरी ने जिस तरह से पहली गेंद से ही सही जगहों पर गेंदबाजी की, उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं।



न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे हमें लगा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है। हमने कुछ कैच छोड़े लेकिन खेल में ऐसा होता है।

उन्होंने कहा, ''जब हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो हमें लगा कि हम आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से गेंद अंदर-बाहर स्विंग हो रही थी, उससे आप यह तय नहीं कर सकते थे कि किस तरह खेलना है। हमारे किसी भी बल्लेबाज ने अपना विकेट इनाम में नहीं दिया। सभी अच्छी गेंद पर आउट हुए।'' भारतीय कप्तान ने कहा, ''हमें इस हार को भूलकर यह विश्लेषण करना होगा कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में क्या गलत हुआ। हमने दो मैच जीते हैं और अब हमें नए सिरे से मैदान पर उतरना होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश थे, हालांकि उन्हें लगा कि शुरुआत में वे प्रतिस्पर्धी स्कोर से लगभग 20 रन पीछे रह गए थे। हेनरी की अगुवाई में गेंदबाजों ने विकेट लेकर इसकी भरपाई कर दी। उन्होंने कहा, ''मैं इस जीत से काफी खुश हूं। दोबारा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, इसलिए बहुत खुश हूं। यंग ने शानदार बल्लेबाजी की और विकेट गंवाने के बावजूद हमने अच्छा स्कोर बनाया। हम वैसे 360 रन बनाने की सोच रहे थे। हेनरी आज खेलना चाहता था। नई गेंद से और थोड़ी मददगार विकेट पर वह सबसे अच्छा गेंदबाज है।'' हेनरी ने अभ्यास के दौरान साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे से टक्कर होने के कारण सिर में लगी चोट के बाद वापसी की। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने सही स्थान पर गेंद करने पर ध्यान दिया जिससे उन्हें फायदा मिला।

### पुष्पा का किरदार निभाने से मेरा खुद पर भरोसा और मजबूत हुआ है : करुणा पांडे

**मुंबई।** सोनी सब का पुष्पा इम्पॉसिबल एक ऐसी महिला की कहानी के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है, जो साहस, सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करती है। वर्षों से पुष्पा का सफर अनगिनत महिलाओं को खुद पर विश्वास करने, सही के लिए आवाज़ उठाने और तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहा है। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखने और उनमें से ताकत खोज लेने की पुष्पा की क्षमता ने उन्हें कई लोगों के लिए प्रेरणा का एक भरोसेमंद स्रोत बना दिया है। इस सफर ने करुणा पांडे पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो पिछले चार वर्षों से अधिक समय से पुष्पा के किरदार को जीवंत कर रही हैं। इस दौरान, अभिनेत्री का इस किरदार के साथ एक गहरा जुड़ाव बन गया है और उन्होंने इससे जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं, जिन्होंने उनके अपने दृष्टिकोण को भी आकार दिया है। करुणा के लिए, पुष्पा का किरदार निभाना एक ऐसा सीखने वाला अनुभव रहा है, जो एक कलाकार के रूप में उनके काम से कहीं आगे जाता है। इस किरदार ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है और उन्हें अपनी सोच पर भरोसा करना, अपने फैसलों पर विश्वास रखना और जो सही लगे उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहना सिखाया है। वे भी पुष्पा की तरह छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूँढ लेती हैं और जीवन के अनुभवों से ताकत हासिल करने की उसकी क्षमता की प्रशंसा करती हैं। वर्षों के दौरान यह जुड़ाव इतना खास हो गया है कि करुणा हर दिन सेट पर आने के लिए उत्साहित रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक बार फिर पुष्पा की दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। सीखे गए जीवन के सबकों के बारे में बात करते हुए, करुणा पांडे ने साझा किया, पुष्पा का किरदार निभाने से मेरा खुद पर भरोसा और मजबूत हुआ है।



# आईसीआईसीआई लाइफ बीएसई 500 मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च

**मुंबई (ए)।** आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई लाइफ बीएसई 500 मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह नया इक्विटी निवेश विकल्प कंपनी की ज्यादातर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) के साथ उपलब्ध होगा। इस फंड के माध्यम से निवेशकों को मजबूत वित्तीय स्थिति और शेयर की कीमतों में सकारात्मक रुझान वाली कंपनियों में निवेश करने का अवसर मिलेगा।

यह इंडेक्स फंड निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके तहत बीएसई 500 की सूची में शामिल 50 ऐसे शेयरों का विविध पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जो दो प्रमुख मानकों- मोमेंटम और क्वालिटी पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। फंड के लॉन्च पर आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष कुमार ने कहा, आईसीआईसीआई लाइफ बीएसई 500 मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड निवेशकों को मजबूत कारोबारी मॉडल, कमाई की बेहतर संभावनाओं और शेयर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी वाली कंपनियों में निवेश के माध्यम से लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का प्रभावी अवसर देता है। खास बात यह है कि निवेशकों को ऐसी कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश का मौका मिलेगा, जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है। कंपनियों का चयन रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी और प्रति शेयर आय (ईपीएस) जैसे वित्तीय मानकों के आधार पर किया जाता है। साथ ही, इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में पिछले 12 महीनों के दौरान अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, यह इंडेक्स फंड बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहकों को लंबी अवधि के निवेश से मिलने वाले कंपाउंडिंग के लाभ का फायदा उठाने में सक्षम बनाने की कंपनी की रणनीति के अनुरूप है।

# आईडीबीआई इनोवेट 2026 : आईडीबीआई बैंक ने किया भव्य ग्रैंड फिनाले का समापन

**मुंबई (ए)।** आईडीबीआई बैंक ने अपनी प्रमुख हैकाथॉन पहल आईडीबीआई इनोवेट 2026 के ग्रैंड फिनाले का सफलतापूर्वक समापन किया। यह आयोजन बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने, फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और नवाचार को बढ़ावा देने की बैंक की कोशिशों का एक हिस्सा है।



बिल्ड. इंटीग्रेट. ट्रांसफॉर्म. थीम पर आधारित इस हैकाथॉन ने स्टार्टअप्स, फिनटेक कंपनियों, कामकाजी पेशेवरों और इनोवेटर्स को एक मंच दिया। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की व्यावसायिक और परिचालन चुनौतियों को दूर करने के लिए सुरक्षित, बड़े स्तर पर काम आने वाले और ग्राहकों के अनुकूल समाधान तैयार करना था। इस आयोजन में चार मुख्य विषय शामिल थे, जिसे देशभर से शानदार प्रतिक्रिया मिली।

विजेताओं का चयन तकनीकी जांच, समाधानों के प्रदर्शन, बैंक के सैंडबॉक्स पर परीक्षण और जूरी रिव्यू जैसी कई कड़े पैमानों से गुजरने के बाद किया गया। सभी ट्रैक के विजेताओं और उप-विजेताओं को 03 नवंबर, 2026 को आयोजित ग्रैंड फिनाले में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ श्री राकेश शर्मा ने कहा कि बैंक को भविष्य के लिए तैयार और मजबूत बनाने में नवाचारों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंक का मुख्य ध्यान नई तकनीकों का इस्तेमाल कर ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने और अपनी डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर है। इसके साथ ही बैंक सुरक्षा और बैंकिंग नियमों के पालन के उच्चतम मानकों को भी बनाए रख रहा है। ग्रैंड फिनाले में विजेता और उप-विजेता टीमों ने अपने नए विचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया।

# एनएसई ने निवेशकों और ट्रेडिंग सदस्यों के लिए वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर जोड़े नए डिजिटल फीचर्स

**मुंबई।** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर कई नए फीचर्स जोड़े हैं। इनका उद्देश्य निवेशकों और ट्रेडिंग सदस्यों के लिए शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी को आसानी से उपलब्ध कराना और डिजिटल सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

इसमें एक प्रमुख फीचर एनएसई मार्केट लेंस का बीटा वर्जन है, जो वेब और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध होगा। यह शेयर्स को खोजने और उनकी स्क्रीनिंग करने का प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से निवेशक पहले से तैयार लोकप्रिय स्टॉक स्क्रीन देख सकते हैं, अलग-अलग सेक्टर के शेयर्स की जानकारी ले सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्रीन बना सकते हैं। इसमें सामान्य भाषा में सवाल लिखकर भी शेयर्स की स्क्रीनिंग की जा सकती है। यह सुविधा निवेशकों के सवालों को ऐसे फिल्टर में बदल देती है, जिन्हें वे अपनी जरूरत के अनुसार एडिट कर सकते हैं।

## ►► न्यूज ब्रीफ

### वोट चोरी, बेलगाम महंगाई और जनसमस्याओं के खिलाफ कांग्रेस की जनचौपाल आज

**जांजगीर चाम्पा।** लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई तथा आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जांजगीर द्वारा शनिवार, 14 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे शारदा चौक, जांजगीर में जनचौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस जनचौपाल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों, चुनावी प्रक्रिया में कथित वोट चोरी, महंगाई दर में आश्चर्यजनक वृद्धि तथा आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर जनसंवाद किया जाएगा। कांग्रेसजन आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं, चिंताओं और सुझावों को सुनेंगे तथा लोकतांत्रिक तरीके से जनहित की आवाज बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामविलास राठौर एवं महामंत्री-प्रवक्ता अनिल कुमार राठौर ने जिला कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों एवं प्रभारियों, महिला कांग्रेस, नगर एवं ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों, सेक्टर, जोन एवं बूथ प्रभारियों सहित समस्त कांग्रेसजनों से अपने साथियों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने की अपील की है।

### सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में आयोजित होगी क्विज प्रतियोगिता आज

**जांजगीर।** क्विज प्रतियोगिता एवं 10 एवं 12 बोर्ड परीक्षा में शाला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विकासखंड स्तरीय कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी करेंगे सम्मानित विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने, उनमें सामान्य ज्ञान एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से तत्कालीन कलेक्टर श्री ओपी चौधरी जी द्वारा सत्र 2014 में प्रारंभ किए गए युवा - संकल्प से विकल्प* कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कैरियर मार्गदर्शन एवं विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिर्रा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान विकासखंड की हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलो में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा एवं 10 एवं 12 बोर्ड परीक्षा में शाला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी सम्मानित होंगे। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बम्हनीडीह श्री बसंत चतुर्वेदी द्वारा विकासखंड के समस्त प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। जारी निर्देश के *14 नवंबर को सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलो में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी*। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम एवं शाला का नाम सहित आवश्यक जानकारी 14 नवंबर को ही प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक ग्रुप में अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीईओ बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको शैक्षणिक एवं कैरियर संबंधी संभावनाओं को नई दिशा देना है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, ज्ञान एवं प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

# मड़ई-मेला छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है : महंत

### आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित, अंगार मोती माता मंदिर का किया लोकार्पण

**समवेत शिखर संवाददाता**



**जांजगीर-चांपा।** ग्राम पंचायत भरेंगा (रायपुर)में आयोजित भव्य मड़ाई मेला मिलन समारोह में महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर उन्होंने अंगार मोती माता मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि - *मड़ाई मेला छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। मड़ाई केवल मेला नहीं है, यह हमारे गाँव की परंपरा, भाईचारा और आस्था का प्रतीक है। इस मेल-मिलाप से हमारे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं* उन्होंने श्री रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा कि- जहाँ सुमति तहं संपति नाना, जहाँ कुमति तहं विपति निदाना। जहाँ सुमति होती है, वहाँ सुख-समृद्धि अपने आप आ जाती है और जहाँ कुमति होती है, वहाँ विपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता है। इस अवसर पर गाँव की सेवा में समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शाल, श्रीफ्ल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रूप में उपस्थित दाऊ महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गाँव की माताओं और बच्चों की सच्ची सेविका हैं। इस दौरान अतिथियों ने अंगार मोती माता मंदिर का लोकार्पण कर माता का दर्शन-पूजन किया और समस्त क्षेत्रवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

कार्यक्रम में अजय तिवारी, निर्मल दास वैष्णव, गांव के सरपंच, जनपद सदस्य प्रतिनिधि, सभी पंचगण, प्रतिष्ठित नागरिक, सभी माताएं-बहनें और युवा उपस्थित थे।

# संपूर्ण संसार का भरण-पोषण करती हैं माता लक्ष्मी : महन्त



### अमोदी में माता लक्ष्मी की महा आरती में सम्मिलित हुए महामंडलेश्वर जी, नवधा भक्ति का भी किया शुभारंभ

**समवेत शिखर संवाददाता**

**जांजगीर-चांपा।** ग्राम अमोंदी (कटगी )में आयोजित माता लक्ष्मी की महा आरती में महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। ग्राम वासियों के द्वारा बाजे -गाजे एवं आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। माताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर माता लक्ष्मी की महा आरती की और सुख-समृद्धि की कामना की। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि - *माता लक्ष्मी संपूर्ण संसार का भरण-पोषण करती हैं। जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वहाँ धन, धान्य, सुख और शांति का वास होता है। माता की आराधना से ही घर-परिवार में समृद्धि आती है। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है।* पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने भी लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर विशेष रूप से हेमंत दुबे, निरंजन लाल अग्रवाल, योगेश शर्मा, सुखराम दास, भुवन डड़सेना, चन्दराम यादव, शंकर साहू, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव सहित अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का विधिवत संचालन संतोष यादव ने किया। उल्लेखनीय है कि इसके पश्चात उन्होंने ग्राम कुम्हारी(टुण्ड्रा )पहुंचकर नवधा भक्ति का भी शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। यहां भी लोगों के द्वारा अतिथियों का अत्यंत ही आत्मीयतापूर्ण स्वागत किया गया।

# सीएमएचओ बिलासपुर का कारनामा

### सीएमएचओ ने पेंशनर प्रकरणों का बीएमओ का अधिकार छीना, पेंशनर होंगे परेशान, स्वास्थ्य.पेंशनर संघ ने किया विरोध

**समवेत शिखर संवाददाता**

**जांजगीर-चांपा।** सीएमएचओ बिलासपुर अपने आदेश दिनांक 04.11.2026 को पेंशन प्रकरण निपटारा करने के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के अधिकार को अपने अधीन करने का आदेश जारी किया गया है।

शासन से सभी बी एम ओ आहरण संवितरण अधिकारी होते है, उनका अपना अलग ट्रेजरी कोड और आई डी अलग होता है और सीएमएचओ का अलग होता है।

पेंशन प्रकरण का अधिकार वित्त विभाग द्वारा सभी बी एम ओ (डी डी ओ ) को जारी होता है, इसका अधिकार सीएमएचओ कार्यालय द्वारा नहीं जारी किया जा सकता। वित्त विभाग के नियमों को सीएमएचओ बिलासपुर को परिवर्तन कर अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पेंशनरों को आर्थिक बोझ में डाला जा रहा है । शासन द्वारा विकासखंड स्तरीय अधिकारियों (डी डी ओ)को पेंशन निराकरण के अधिकार दिये गये है इससे पेंशनर, कर्मचारी और आम जनता को शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं का लाभ ब्लॉक मुख्यालय में ही मिलता है । इससे जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ता । वित्त विभाग द्वारा जारी अधिकार को सीएमएचओ को बदलने का अधिकार ही नहीं है। ब्लॉक के सभी कर्मचारियों का कार्मिक संपदा की पूरी जानकारी, बी एम ओ के ट्रेजरी कोड ,आई डी में ही इन्द्राज रहता है । सीएमएचओ अपने कार्यालय के आई डी से दूसरे डी डी ओ के पेंशन प्रकरण कैसे और किस नियम से निपटारा करेगा... सीएमएचओ बिलासपुर का यह कृत्य वित्त विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है।

वर्तमान नियमों के अनुसार जो अधिकारी पेंशन प्रकरण लंबित करेंगे उन पर वित्त विभाग के नियमानुसार कार्यवाही होगा। सीएमएचओ बिलासपुर बी एम ओ (डीडीओ )का अधिकार जिला कार्यालय में सेंट्रलाइज्ड नहीं कर सकता....सीएमएचओ बिलासपुर के इस आदेश को निरस्त करने हेतु स्वास्थ्य पेंशनर कल्याण संघ द्वारा आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य , संयुक्त संचालक स्वास्थ्य बिलासपुर, संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन से निरस्त करने और उनके विरुद्ध विभागीय जांच करने की मांग भी किया जायेगा ।प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर के थवाईत ने आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य , संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन बिलासपुर को सीएमएचओ बिलासपुर के इस अवैधानिक आदेश को तत्काल निरस्त करने हेतु वाट्सअप में निवेदन कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बिलासपुर सीएमएचओ कार्यालय द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार के निर्देश जारी हुआ था जिसे पेंशनर संघ के विरोध के बाद निरस्त किया गया था ।

बिलासपुर सीएमएचओ कार्यालय में पेंशन शाखा में अनेक वर्षों से एक ही कर्मचारी कार्यरत है, जबकि तीन वर्षों में लिपिकों का शाखा परिवर्तन का नियम है। बिलासपुर सीएमएचओ कार्यालय के इस अवैधानिक आदेश को निरस्त करने और सीएमएचओ बिलासपुर के विरुद्ध विभागीय जांच की मांग को लेकर दीपावली बाद ,विभागीय सचिव / संचालक स्वास्थ्य ,आयुक्त और कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन भी दिया जायेगा।

# कृषक उन्नति योजना-किसानों के लिए खुशियों की सौगात : पाण्डेय

**समवेत शिखर संवाददाता**

**जांजगीर-चांपा।** छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर रवि पाण्डेय ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कृषक उन्नति योजना को किसानों के लिए खुशियों की सौगात बताते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।



इंजीनियर रवि पाण्डेय ने जानकारी देते हुये बताया की कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानो को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी । वहीं निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में बची हुई धान की मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी।

उन्होंने इस योजना को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में डीएसएस (डिजिटल क्रॉप सर्वे) के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है और किसान केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं शेष 6 क्विंटल धान पर 3100 रुपये और 2441 रुपये के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 3,954 रुपये बोनस मिलेगा। इस प्रकार किसान को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की सुविधा के साथ शेष मात्रा पर भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।

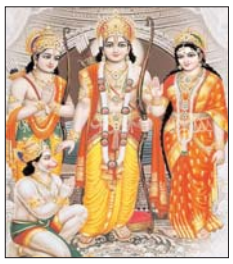
इंजीनियर रवि पाण्डेय ने बताया कि योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि धान का विक्रय नहीं करने वाले किसान भी डीएसएस में दर्ज धान के रकबे और फसल के आधार पर सहायता राशि पाने के पात्र होंगे। इसके लिए किसान को शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। योजना के तहत अधिकतम आदान सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित की गई है।

इंजीनियर रवि पाण्डेय ने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में एक सराहनीय कदम है इससे किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने के अनावश्यक दबाव से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार धान का विक्रय कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अंत में उन्होंने किसान हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ सरकार का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

# अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ 22 से

### कलश यात्रा, देव मूर्तियों की स्थापना के साथ प्रारंभ होगा भव्य आयोजन

**समवेत शिखर संवाददाता**



**जांजगीर-चाम्पा।** जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती स्थित नवनिर्मित चबुतरा भगत चौक में सैकड़ो वर्ष पुराने प्राचीन वट वृक्ष के नीचे मोहल्लावासियों द्वारा विगत वर्षों की भांति 65 वें वर्ष पर अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ का आयोजन आगामी 22 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किया जायेगा।

राम नाम सप्ताह यज्ञ के प्रारंभ दिवस 22 नवम्बर को भगत चौक पुरानी बस्ती संकीर्तन स्थल से कलश यात्रा कीर्तन मण्डली के साथ भगवती देवी दाई मंदिर भीमा तालाब तक निकाली जावेगी। तत्पश्चात वरूण कलश पूजन कर, कलश यात्रा संकीर्तन स्थल वापस होगी। साथ ही यज्ञ प्रारंभ हेतु देव आवाह्न, स्थापना पूजा एवं स्वास्ति वाचन के साथ देव मूर्तियों की झांकी स्थापना की जावेगी। विदित हो कि भगत चौक पुरानी बस्ती में 100 साल से अधिक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे चबूतरे में पूरे सात दिन और सात रात राम नाम का जाप लगातार किया जाता है। वही जिले व अन्य जिलों के गांवों से कीर्तन मण्डली रामनाम की गायन करने मण्डली सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए, जो घण्टो यज्ञ स्थल पर राम नाम का रसपास करते है। यज्ञ का समापन 29 नवम्बर को किया जावेगा और उसी शाम भव्य नगर यात्रा भी निकाली जावेगी। जहां श्रीकृष्ण राधा को पालकी में ऊठा पूरे नगर का भ्रमण कराया जावेगा। वहीं 30 नवंबर को हवन, सहस्त्र धारा, ब्राम्हाण भोज का आयोजन किया जावेगा। आयोजन की तैयारी में आयोजन समिति के संस्थापक, संरक्षक, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, प्रचार-प्रसार अध्यक्ष, व्यवस्थापकगण, पुराजीगण, मंच संचालन प्रभारी सहित भगत चौक के मोहल्लावसी जुटे हुए है। अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ का पूरा पूजन कार्य उपाध्याय परिवार द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। गौरतलब है कि इस वर्ष भगत चौक में अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ को लेकर आयोजन समिति सहित पूरे भगत चौक मोहल्लेवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

# जनजातीय समाज भारत की आत्मा है : चिंतामणि महाराज

### जनजातीय समाज 2047 के विकसित भारत का बनेगा मजबूत आधार

**समवेत शिखर संवाददाता**



**अंबिकापुर।** सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ जनजातीय समाज विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार बन रहा है।

संकल्प भवन भाजपा कार्यालय अम्बिकापुर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए चिंतामणि महाराज ने कहा कि भगवान बिरसा मुण्डा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर जल, जंगल, जमीन और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। 15 नवम्बर 1875 को झारखंड के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुण्डा ने 'उलगुलान' महाक्रांति का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' का नारा दिया। उनके बलिदान और संघर्ष ने जनजातीय अधिकारों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया।

भाजपा कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के अंतर्गत आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, केन्द्र सरकार की योजनाओं और विकसित भारत 2047 के विजन की जानकारी दी।

मंचासीन भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, महापौर मंजूषा भगत, पूर्व सांसद कमलभान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फूलेश्वरी सिंह, महामंत्री अरुणा सिंह, संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, देवनाथ सिंह पैकरा एवं बिन्देश्वरी पैकरा की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लगभग एक सदी पहले ही तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे जनजातीय नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया था। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के अनुयायियों का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली अध्याय है।

चिंतामणि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर भगवान बिरसा मुण्डा के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री ने उलिहातू पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पीएम जनमन अभियान का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों का गठन किया। वहीं मोदी सरकार में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं।

उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन अधिकार पट्टा, पेसा कानून, आयुष्मान भारत और सिकल सेल उन्मूलन मिशन जैसी योजनाओं से जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझा। जनजातीय नायकों को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया और जनजातीय कल्याण के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आरक्षण, समान नागरिक संहिता और जनजातीय अधिकारों को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया।

आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों में जनजातीय गौरव सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, युवा संवाद, छात्रावास संपर्क अभियान और जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि सहित विभिन्न आयोजन होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक जनजातीय समाज को विकसित भारत की यात्रा का समान भागीदार बनाना है। इसके लिए जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और जनजातीय भाषाओं एवं संस्कृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए चिंतामणि महाराज ने 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुण्डा एवं क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की।

# रंगीन रोशनी से जगमगाया पूरन तालाब छठ घाट, महापर्व को लेकर भोजपुरी समाज की तैयारियां पूरी

### कल खरना के साथ शुरू होगी छठ महापर्व की विशेष पूजा, 15 नवंबर को अस्ताचलगामी और 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, आस्था और उत्साह से सराबोर हुआ पत्थलगांव

**समवेत शिखर संवाददाता**

**पत्थलगांव।**लोक आस्था, सूर्य उपासना और अटूट श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा को लेकर पत्थलगांव में उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है। पत्थलगांव भोजपुरी समाज द्वारा छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर के प्रसिद्ध पूरन तालाब छठ घाट को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पूरे घाट परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे तालाब का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। घाट की सजावट और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के साथ ही भोजपुरी समाज के लोगों में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।

हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना को समर्पित है। इस पर्व की सबसे खास परंपरा यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। जहां दुनिया उगते सूर्य को नई ऊर्जा और सफलता का प्रतीक मानती है, वहीं छठ महापर्व ढलते सूर्य को भी समान श्रद्धा और सम्मान देने का संदेश देता है।

**36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत, संतान की सुख-समृद्धि की कामना-**छठ पूजा में व्रती महिलाएं और पुरुष परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना के लिए कठिन व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इस महापर्व में व्रती लगभग 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सूर्य देव एवं छठी मैया की आराधना करते हैं।




चार दिनों तक चलेगा आस्था का महापर्व छठ महापर्व के चारों दिनों का अपना विशेष महत्व है। 14 नवंबर, शनिवार ङ्क खरनाः महापर्व के दूसरे दिन खरना की पूजा होगी। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर तथा रोटी का पवित्र प्रसाद तैयार कर पूजा करते हैं। परंपरागत रूप से आम की लकड़ी से बने नए मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार किया जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती लगभग 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं।

15 नवंबर, रविवार ङ्क संध्या अर्घ्यः छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, नारियल, फल एवं अन्य पूजन सामग्री सजाकर छठ घाट पहुंचेंगे। यहां डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे।

16 नवंबर, सोमवार ङ्क उषा अर्घ्य एवं पारणः महापर्व के अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही चार दिवसीय छठ पूजा का समापन होगा। व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली एवं संतान की दीर्घायु की कामना करेंगे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर पारण किया जाएगा और निर्जला व्रत संपन्न होगा।

**आस्था के साथ स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक एकता का संदेश-**छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस पर्व में साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा में प्राकृतिक फल, बांस से बने सूप-दउरा और पारंपरिक प्रसाद का उपयोग किया जाता है। इस पर्व की एक विशेषता यह भी है कि महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर घाटों की साफ-सफाई, सजावट और पूजा की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं।

पत्थलगांव के पूरन तालाब छठ घाट पर भी यही सामूहिक आस्था और सामाजिक एकता देखने को मिल रही है। भोजपुरी समाज की तैयारियों के बीच अब श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की पावन बेला का इंतजार है। रंगीन रोशनी से सजा घाट, पारंपरिक छठ गीतों की गूंज और सूर्य उपासना का अद्भुत दृश्य एक बार फिर पत्थलगांव में लोक आस्था और भक्ति का अनुपम संगम प्रस्तुत करेगा।

# लखनपुर नगर पंचायत में कागजों की जंग पहुंची मारपीट तक, बस स्टैंड में सीएमओ से गाली-गलौज और हाथापाई का आरोप

**समवेत शिखर संवाददाता**

**अंबिकापुर।** लखनपुर नगर पंचायत लखनपुर में पिछले दो वर्षों से चल रही शिकायतों और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति अब सड़क पर मारपीट तक पहुंच गई है।

नगर पंचायत में निर्माण कार्यों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर नगर पंचायत उपाध्यक्ष एवं उनके पति द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों और सीएमओ की ओर से दिए जा रहे जवाबों के बीच विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। शुक्रवार को नगर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में नगर पंचायत उपाध्यक्ष के पति सनी बंसल पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।मिली जानकारी के अनुसार, आगामी छठ पर्व को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी नगर में साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान प्रतीक्षा बस स्टैंड में नगर पंचायत उपाध्यक्ष नेहा सनी बंसल के पति सनी बंसल और सीएमओ के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज के साथ मारपीट की नौबत आ गई। आरोप है कि सनी बंसल ने सीएमओ के साथ मारपीट की, जिसके बाद सीएमओ ने पास स्थित पान ठेले में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दिनदहाड़े सार्वजनिक स्थल पर हुई इस घटना की चर्चा पूरे नगर में हो रही है।घटना के बाद दोनों पक्ष लखनपुर थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आवेदन सौंपा है।